नई दिल्ली
शुक्रवार
09 अक्टूबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 36
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

नाना पाटेकर के निधन पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष...पेज-06

DELHIN/2014/58158

एक करोड़ परिवारों को उद्यमी परिवार...पेज-05

एक नजर

एयर इंडिया विदेश जाने वाले यात्रियों को 'ट्रैवल सिम कार्ड' देगी

नई दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया विदेश जाने वाले यात्रियों को 'ट्रैवल सिम कार्ड' देगी। एयर इंडिया के ब्रांड वाला ट्रैवल सिम कार्ड 'ईजीरोम' टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। विमानन कंपनी के मुताबिक यह अतिरिक्त उत्पाद एयर इंडिया के ब्रांड वाले एक समर्पित वेबपेज पर भौतिक सिम कार्ड के साथ-साथ ई-सिम के रूप में खरीद के लिए उपलब्ध होगा। इस सिम कार्ड के जरिये यात्री अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मौखिक एवं डेटा सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। शुरुआत में सिम कार्ड मुफ्त दिया जाएगा, जबकि रोमिंग पैक के लिए शुल्क देना होगा। यह उत्तर अमेरिका, यूरोप (ब्रिटेन समेत), ऑस्ट्रेलिया, एशिया-प्रशांत और पश्चिम एशिया के 30 देशों में उपलब्ध होगा। कंपनी ने बताया कि ईजी रोम सिम के साथ हमारे कस्टमर एयर इंडिया के लगभग 30 डेस्टिनेशन पर भरोसेमंद और तेज-स्पीड वाली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का फायदा उठा सकते हैं। इसमें 1 जीबी तक मुफ्त डेटा और इंटरनेशनल रोमिंग पर 50 फीसदी तक की बचत भी मिलती है। कंपनी ने कहा कि भरोसेमंद पार्टनर टाटा ज्यटाटाट्टकॉम का 'ईजीरोम' सिम विदेश यात्रा शुरू होते ही कनेक्टेड रहना आसान बनाता है।

नाना पाटेकर के निधन पर प्रमुख हस्तियों ने जताया शोक,अर्पित की श्रद्धांजलि

नई दिल्ली,एजेंसी। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के आकस्मिक निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती मुर्मु ने श्री पाटेकर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपने सशक्त और प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से उन्होंने मानवीय अनुभवों के विविध आयामों को जीवंत किया और ऐसे पात्रों को पर्दे पर उतारा, जिन्होंने लोगों के दिलों-दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा के प्रति श्री पाटेकर की प्रतिबद्धता वंचितों के प्रति उनकी चिंता को दर्शाती है। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री मोदी ने कहा कि नाना पाटेकर देश की आन, बान और शान के लिए जीने वाले कलाकार थे। उन्होंने कहा कि श्री पाटेकर ने अलग-अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता और अपनी फिल्मों के जरिए समाज में व्याप्त अव्यवस्था पर करारा प्रहार किया। श्री मोदी ने उनकी तेज वाणी और प्रभावशाली खामोशी का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों तथा चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। डॉ भागवत ने कहा कि अभिनेता के रूप में नाना पाटेकर ने अपनी अलग पहचान बनाई। अपने लंबे कलात्मक जीवन में उन्होंने अभिनय में उत्कृष्टता के साथ-साथ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक विषयों पर लोगों को सकारात्मक चर्चा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने श्री पाटेकर के शोक संतप्त परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी उनके निधन पर शोक जताया। श्री गांधी ने नाना पाटेकर के निधन को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि अपने अभिनय और किरदारों के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा और दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी।

मैं गलत कामों को बंद करने की ठान कर बैठा हूं, बंद कर के रहूंगा: मोदी

नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता का लाखों करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया है और बहुतों की मुफ्त की कमाई बंद की है और ऐसे ही लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत कामों को बंद करने की ठान रखी हैं और ऐसा करके रहेंगे चाहे उनका विरोध करने वाले कितना ही शोर क्यों न करें। मोदी यहां यशोभूमि में भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 का औपचारिक उद्घाटन कर रहे थे। उनका यह बयान ऐसे वातावरण में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जबकि विपक्ष राज्यों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कार्यक्रम को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह- धरने प्रदर्शन कर रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर हैं। सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशरीज़ के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल में भेजे गए और उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। और इससे करीब 5 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। मोदी ने कहा, '' अब मुझे बताइए, जिनकी ये मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो क्या, मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो कितने ही चिल्लाते रहें, चीखते रहें, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा।' श्री मोदी ने कहा कि टेलीकॉम के क्षेत्र में भारत में पिछले 10-12 साल में जो क्रांति आई है उसका नागरिक को सीधा-सीधा फायदा हुआ है। उन्होंने देश विदेश से आयी दूरसंचार जगत की हस्तियों को संबोधित करते हुए कहा, '' आप जानते हैं कि भारत, भाषा और भूगोल, हर प्रकार से डायवर्स देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके कारण लोगों के जीवन में अनेक असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी ने इस डायवर्सिटी (विविधता) को भी सुविधा से जोड़ा है। पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे। यानि कुछ भी काम करना हो, सरकारी सेवा लेनी हो, तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है। ' उन्होंने कहा, '' पुरानी व्यवस्था होती, तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता, मोदी ने इसको रोका है। और अब वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है। श्री मोदी ने कहा, ''पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं। किसान को मोबाइल फोन पर ही पैसा जमा होने का मैसेज मिल जाता है। ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है, जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का लाभ पहुंच ही नहीं पाता था।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरसंचार की चर्चा में अक्सर नेटवर्क और स्पैक्ट्रम पर बहस , मोबाइल टावर, नेटवर्क की पहुंच और गति की बातें होती हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए टेलीकॉम के मायने और भी रहे हैं। बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन आधुनिक संचार के माध्यम के साथ-साथ गुड-गवर्नेंस (सुशासन) का भी अहम औजार बनकर सामने आया है। और यह हमारे डिजिटल इंडिया विजन के केंद्र में रहा है।

जीएसटी कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान समाप्त करने का फैसला

जीएसटी 2.0 में प्रक्रिया आसान बनाने पर बल

नई दिल्ली,एजेंसी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने और आपराधिक मुकदमा चलाने संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसने जीएसटी प्रक्रियाओं और नियमों के अनुपालन में व्यापक सुधार करने की सिफारिशें की हैं। केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में ये फैसले लिये गये। यह बैठक गत वर्ष सितंबर की बैठक के बाद पहली बार आयोजित की गयी थी। पिछली बैठक जीएसटी की दरों और कर ढांचे में व्यापक सुधार के लिए याद की जाती है जबकि इस बार -प्रक्रिया और अनुपालनों में सुधार पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद की 57वीं बैठक की सिफारिशें अगले साल पहली अप्रैल से लागू की जाएंगी।

आज के एजेंडा में आपूर्ति श्रृंखला किसी स्तर पर किसी इकाई द्वारा कर दायित्व में चूक करने पर जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट में व्यवधान को दूर करने तथा केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के तहत बहुराष्ट्रीय इकाइयों के लिए सिंगल विंडा सुविधा शुरू करने के मुद्दे को अधिकारियों की समित को दिया गया है। जिसकी सिफारिश तीन महीने में आ जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी की दरों की समीक्षा के लिए अब हर वर्ष जीएसटी परिषद की अलग बैठक होगी। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी के तहत गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही न्यूनतम सजा का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। देरी से रिटर्न फाइल करने के लिए मूल कर राशि की वसूली, ब्याज और जुर्माने से ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने के कारण कई करदाताओं को अभी अलग-अलग रिटर्न भरने होते हैं।

सीजीएसटी के तहत 69.5 लाख करदाताओं में से दो लाख इस श्रेणी में हैं। उनके लिए एकीकृत विंडो बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह अगले वित्त वर्ष से लागू होगा। उन्होंने कहा कि रिफंड क्लेम के एक्नोलेजमेंट में लगने वाले समय को 15 दिन से घटाकर अब 10 दिन कर दिया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए लगने वाले दस्तावेजों के बारे में निश्चितता रहेगी। प्रणाली के जरिये ही इकाइयों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और मदद की जाएगी। छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के जरिये आपूर्ति करने के लिए पंजीकरण सरल किया जाएगा। करदाता पंजीकरण के समय दिए गए विवरण में स्वयं संशोधन कर सकेंगे और पंजीकरण रद्द कराने का आवेदन स्वत: स्वीकार माना जाएगा।

मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अपराधियों को माफ करने की भी सीमा होनी चाहिए

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को गंभीर अपराधों में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामलों पर कड़ी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को 'माफ' करने की एक सीमा होनी चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हर बार नरमी दिखाने और माफ करने की प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं तो रोक लगनी चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि हमारे पास माफ करने के रवैये और 'सबसे दुर्लभ मामलों' (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) के सिद्धांत का बार-बार लाभ दिए जाने के कारण देश में अपराध की स्थिति पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक समय हत्या के मामलों में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत इसलिए लागू होता था, क्योंकि उस समय हत्या के अपराध भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थे लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। एक पुराने केस का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि एक पिता ने अपनी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी। मां की गवाही पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में वह पैरोल पर बाहर निकला और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। न्यायालय ने कहा कि इस बार गवाह उसकी छोटी बेटी थी, जिसके आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि, बाद में उच्चतम न्यायालय ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। तर्क दिया गया कि उसने छोटी बेटी की हत्या नहीं की थी। न्यायालय ने कहा कि इस प्रवृत्ति पर रोक तो लगानी होगी।

राष्ट्रपति व अन्य ने 94वें वायुसेना दिवस पर सैनिकों को दी बधाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई नेताओं ने गुरुवार को 94वें वायु सेना दिवस पर वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मु ने एक्स पर लिखा, ' भारतीय वायु सेना ने अपनी कुशलता, अनुशासन और तैयारी के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए देश की बेहतरीन सेवा की है। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारे एयर वॉरियर्स के साहस, सटीकता और ऑपरेशनल तैयारी को साबित किया। उन्होंने आपदाओं और मानवीय संकटों के समय भी बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। उनका समर्पण देश के लिए प्रेरणा और गर्व का स्त्रोत बना हुआ है। भारतीय वायु सेना सेवा और उत्कृष्टता की अपनी गौरवशाली परंपरा को इसी तरह बनाए रखे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय वायु सेना की वीरता, पेशेवर रवैया और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा देश की संप्रभुता की रक्षा करती है और देश को प्रेरित करती है।

राहुल गांधी समेत इंडी गठबन्धन के सांसद राजघाट पहुंचे, चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन

नई दिल्ली,एजेंसी। राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान इन दिनों दोपहर होते-होते अचानक बढ़ जाता है। वजह है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, जो गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आयोजित लंच के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद तीन बसों में सवार होकर राजघाट पहुंचे।

राजघाट पहुंचकर विपक्षी नेताओं और सांसदों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस की ओर से इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण विरोध के तौर पर पेश किया गया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा था कि विपक्षी सांसद राजघाट जाकर महात्मा गांधी से प्रार्थना करेंगे। विपक्षी दलों का मुख्य आरोप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनावी प्रक्रिया को लेकर है। विपक्षी नेताओं ने इन मुद्दों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। वहीं, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसदों को जंतर-मंतर की ओर जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर भीड़ जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बावजूद विपक्षी सांसद और उनके समर्थक वहां पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी और विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर उनकी आपत्तियों का समाधान किया जाना चाहिए। विपक्ष ने संकेत दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार, निर्वाचन आयोग और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष जहां अपने विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार बता रहा है, वहीं भाजपा और निर्वाचन आयोग विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहे हैं।

सरकार पुरानी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को नए सिरे से विकसित करेगी: प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली/चेन्नई। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को चेन्नई में 'विंडर्जी इंडिया-2026' के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में लगभग 25 गीगावाट क्षमता वाली पुरानी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को नए सिरे से विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रल्हाद जोशी ने देश में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाओं और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशाल अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र ने मजबूत गति प्रदर्शन किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक स्थापना हासिल की गई है। जोशी ने कहा कि हमें विश्वास है कि वार्षिक पवन ऊर्जा स्थापनाएं वित्त वर्ष 2026-27 में इस रिकॉर्ड को पार कर जाएंगी, जो भारत की पवन ऊर्जा यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रमाण होगा।

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सितंबर तक पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 गीगावाट तक पहुंची है। यह निरंतर वृद्धि 2030 तक 100 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की नींव को मजबूत करेगी और भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री जोशी ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का रोडमैप प्रस्तुत किया। इस अवसर पर तमिलनाडु के ऊर्जा संसाधन एवं विधि मंत्री थिरु सी.टी.आर निर्मल कुमार, केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, पवन ऊर्जा संघों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता भी उपस्थित थे। 'विंडर्जी इंडिया-2026' वैश्विक पवन ऊर्जा इकोसिस्टम को एक साझा मंच पर लाया है, जिसमें 20 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 400 प्रदर्शक, 500 प्रतिनिधि और डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन के समर्पित कंट्री पवेलियन (देश-विशिष्ट मंडप) शामिल हैं।

पुणे में आज राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार

मुंबई,एजेंसी। दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का शुक्रवार को पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 75 वर्षीय नाना का गुरुवार तड़के गोवा के पणजी में निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री समेत तमाम नेताओं और फिल्म जगत की हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। नाना के करीबी मित्र गणेश थोराट ने बताया कि पुणे के बाहरी इलाके में स्थित फार्महाउस में नाना का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को ही गोवा से पुणे स्थित फार्म हाउस लाकर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां शुक्रवार शाम करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना के बेटे मल्हार पाटेकर से फोन पर बातचीत कर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने परिवार को सरकार की ओर से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी दी। नाना के मराठी रंगमंच के साथ-साथ हिंदी और मराठी सिनेमा में योगदान को देखते हुए सरकार की ओर से यह सम्मान दिया जा रहा है। नाना के पुत्र मल्हार पाटेकर ने बताया कि नाना अपने गोवा स्थित घर में बेहोशी की हालत में मिले थे। इसके बाद उन्हें तत्काल मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाना का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। अस्पताल से जुड़े चिकित्सक के अनुसार नाना ने करीब ढाई बजे अपने एक दोस्त को संदेश भेजकर तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी दी थी। देर रात होने के कारण दोस्त तत्काल संदेश नहीं देख सके। इसके बाद उन्होंने नाना से संपर्क किया और करीब चार बजे उनके घर पहुंचे। उस समय नाना को काफी पसीना आ रहा था और उनकी हालत बिगड़ रही थी। वह धीरे-धीरे बेहोशी की ओर जा रहे थे। इसके बाद केयरटेकर को अस्पताल भेजा गया और फिर एंबुलेंस से नाना को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। नाना पाटेकर के निधन से हिंदी और मराठी फिल्म जगत में शोक की लहर है। नाना ने गोवा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने की। नाना के निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत की हस्तियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई यादगार किरदार निभाए। गंभीर भूमिकाओं से लेकर खलनायक और हास्य किरदारों तक उन्होंने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी संवाद अदायगी, आवाज और अभिनय का अंदाज दर्शकों के बीच हमेशा खास रहा। नाना की हालिया रिलीज फिल्मों की बात करें तो वह विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी 'ओ रोमियो' में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और फरीदा जलाल प्रमुख भूमिकाओं में थे।

छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : रेखा गुप्ता

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में अंधेरी जगहें, लाइटिंग की कमी, टूटे फूटपाथ और कचरे की समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार देर रात दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंचीं। यहां उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी सुरक्षा, परिवहन, हॉस्टल और कॉलेज से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से बातचीत करते हुए पूछा कि रात में आने-जाने में कोई परेशानी या असुरक्षा तो महसूस नहीं होती और कॉलेज से जुड़ी कोई समस्या हो तो वह भी उन्हें बताएं। उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनकी हर उचित समस्या के समाधान के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कैंपस में निरीक्षण करते हुए कई डार्क स्पॉट देखे और अधिकारियों से मौके पर ही उनकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी होने के बावजूद कैंपस के अंदर कई स्थानों पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि यहां छात्राओं और विद्यार्थियों की लगातार आवाजाही रहती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पेड़ों की अनावश्यक शाखाओं की छंटाई कराने और जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए ताकि पेड़ों की वजह से रोशनी बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर टूटे और असमान फुटपाथ देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फुटपाथ ऐसी स्थिति में नहीं होने चाहिए कि विद्यार्थियों को चलने में परेशानी हो। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखने को कहा और निर्देश दिया कि पूरे मार्ग की जांच कर जहां भी फुटपाथ क्षतिग्रस्त या असमान हैं, उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कैंपस में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने कैमरे लगे हैं, उनमें से कितने काम कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरों की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां सीसीटीवी की आवश्यकता है, वहां जल्द कैमरे लगाए जाएं और पहले से लगे कैमरों की कार्यशीलता की भी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि कैंपस का कोई भी संवेदनशील क्षेत्र निगरानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कैंपस में पीसीआर की मौजूदगी और रात के समय महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में भी पूछा। छात्राओं ने बताया कि रात में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर पीसीआर भी तुरंत पहुंचती है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को आपसी समन्वय से काम करने पर जोर दिया। कैंपस में जगह-जगह गंदगी और खराब ग्रीन बेल्ट देखकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया और तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसा स्थान है जहां हर दिन हजारों विद्यार्थी आते-जाते हैं। इसलिए यहां साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षित रास्ते और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना जरूरी है।

हॉस्टल और पीजी से जुड़ी समस्याओं पर भी मुख्यमंत्री ने छात्राओं से विस्तार से बातचीत की। छात्राओं द्वारा पीजी की स्थिति और सुविधाओं से जुड़ी परेशानी बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द पीजी पॉलिसी लेकर आ रही है, जिससे पीजी व्यवस्था में आवश्यक नियम और मानक तय किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए नए हॉस्टलों के निर्माण और बेहतर हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को रहने के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आर्ट्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, पार्किंग और अन्य संवेदनशील हिस्सों का दोबारा निरीक्षण कर कम रोशनी वाले स्थानों पर आवश्यक सुधार किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण में सामने आई प्रत्येक समस्या का समाधान बिना किसी देरी के किया जाए और दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की बाद में समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर भी बातचीत की और कहा कि छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए और इसके लिए वे थोड़ा समय निकालें।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। आज याचिकाकर्ता और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से पेश वकील संजय घोष इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद न्यायालय ने कल यानि 9 अक्टूबर को सुनवाई का आदेश दिया।

चिब ने दिल्ली पुलिस के एक अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी अर्जी में कहा था कि वह सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करेगा। याचिका में कहा गया है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद पुलिस ने एक अक्टूबर को ही अनुमति न देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित पहली तारीख भी थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि सभाओं को नियंत्रित करने की पुलिस की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि वह हालात का अलग-अलग और उचित आकलन किए बिना पूरी तरह से रोक लगा दे। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का फैसला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन और सभाओं से जुड़े दिशा-निर्देशों को बिना सोचे-समझे लागू किया जाना मनमाना है।

थप्पड़ प्रकरण को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़क के निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस और मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

याचिका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साहिब सिंह ने दायर की है। याचिका में साहिब सिंह ने इस घटना की स्वतंत्र जांच करने और पुलिस सुरक्षा की मांग की है। साहिब सिंह ने याचिका में कहा है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ मारपीट की। याचिका में साहिब सिंह ने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल सुरक्षा की भी मांग की है और आरोप लगाया है कि घटना के बाद उन्हें धमकियां और डराने वाले संदेश मिले हैं। याचिका में मांग की गई है कि इस घटना की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की जाए।

न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करे। याचिका में कहा गया है कि इस घटना की सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संरक्षित रखने का दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में आरोप लगयाया गया है कि घटना के दिन वे विधायक जरनैल सिंह के साथ आउटर रिंग रोड पर सड़क निर्माण के काम का निरीक्षण कर रहे थे, जहां घटिया सामग्री और काम में कमियों के आरोप थे। तभी प्रवेश वर्मा और दूसरे लोगों ने कथित तौर पर उनसे उलझना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया, गालियां दी गई और मारपीट की गई, साथ ही घटना की रिकॉर्डिंग वाला उनका मोबाइल फोन जबरन छीनकर तोड़ दिया गया।

युवा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएं : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं को कभी भी अपने जोश पर होश हावी नहीं होने देना चाहिए। आपकी ऊर्जा, विचार और आकांक्षाएं तभी सार्थक हैं, जब उन्हें जागरूकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना का मार्गदर्शन मिले। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा का भ्रमण करने आए विद्यार्थियों के गुरुवार को संवाद के दौरान कही।

महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल (अहमदाबाद) नवर्चना विद्याणी विद्यालय (वडोदरा) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। यह भ्रमण युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ने तथा उन्हें भारत की संसदीय परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों और विधायी प्रक्रियाओं से परिचित कराने की विधानसभा की निरंतर पहल का हिस्सा था। इस संवाद ने विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आए छात्रों को विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीधे संवाद करने तथा कक्षा और पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर विधायिका के कामकाज को समझने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा, जिज्ञासा और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन इनका साथ जागरूकता, धैर्य और विवेक से होना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने, सोच-समझकर निर्णय लेने और अपनी क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने आसपास हो रहे बदलावों का केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनमें ऐसी समझ और जिम्मेदारी की भावना विकसित होनी चाहिए, जो उन्हें राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने के योग्य बनाए।

एमसीडी ने दिल्लीभर में जारी प्रवर्तन अभियान के तहत 21 संपत्तियों पर की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

सद्भावना टुडे,संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ पूरी दिल्ली में लगातार प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। निगम के सभी 12 जोन में भवन निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज की विशेष प्रवर्तन कार्रवाई के तहत निगम के सभी 12 जोन में कुल 21 ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां की गईं। इसके अलावा, भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले में 4 संपत्तियों को सील किया गया तथा 4 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लगातार निगरानी रखते हुए चिन्हित उल्लंघनों के खिलाफ निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई। एमसीडी द्वारा कल भी प्रवर्तन अभियान के तहत 27 ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां की गई थीं तथा 3 संपत्तियों को सील किया गया था। यह कार्रवाई भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ निगम द्वारा लगातार और प्रभावी प्रवर्तन को दर्शाती है। आज की प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान रघुबीर नगर, संत नगर, गुरमंडी राजपुरा, कल्याण विहार सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां की गईं। एमसीडी ने दोहराया कि निगम के क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने तथा एमपीडी, भवन उपनियमों और अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी का यह प्रवर्तन अभियान सभी 12 जोन में अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम पैदा करने वाले अन्य उल्लंघनों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा।

दिल्ली में 9-11 अक्टूबर को सभी पोलिंग बूथों पर लगेंगे कैंप, 5 लाख से ज्यादा नो- मेपिंग व तार्किक विसंगति मामलों का हुआ निपटारा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत छूटे मतदाताओं को जुड़ने के लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों पर 9 और 11 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए 7 और 8 अक्टूबर को विशेष कैंप लग रहे हैं। इससे पहले 29 और 30 सितंबर को भी ऐसे कैंप लगे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को एक नोट करते हुए बताया कि अब तक 15,30,408 नो- मेपिंग और तार्किक विसंगति मामलों का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करके निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ खुद घर जाकर नोटिस वाले मतदाताओं से दस्तावेज ले रहे हैं, उन्हें दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। सभी दावे-आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर तक कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी से पात्रों से अपने निवास स्थान के बूथ पर जाकर नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के 1 अक्टूबर के आदेश के बाद बीएलओ घर-घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं और फार्म-6 भरवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, जो जो मतदाता दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और एएसडीडी लिस्ट में हैं, वे भी फार्म-6 भर सकते हैं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (31 अगस्त को प्रकाशित) में नहीं है, तो आप 30 अक्टूबर के बीच फार्म-6 भर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

निगमायुक्त ने मोलड़बंद क्षेत्र का किया निरीक्षण, जनसमस्याओं के त्वरित एवं स्थायी समाधान के दिए निर्देश

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, संजीव खिरवार ने आज मोलड़बंद क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, जलभराव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अतिक्रमण, कूड़ा प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पार्षद श्री हेमचंद गोयल, सेंट्रल जोन के उपायुक्त डॉ सचिन गुप्ता तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान मोलड़बंद गांव स्थित एमसीडी प्राथमिक विद्यालय की स्थिति का विशेष रूप से जायजा लिया गया। विद्यालय के कुछ कमरों में मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को क्षतिग्रस्त कमरों की आवश्यक मरम्मत का कार्य आगामी सोमवार तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरम्मत कार्य पूरा होने तक विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे और बच्चों को अस्थायी रूप से सुरक्षित वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए। इसके अलावा निगमायुक्त ने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए बेहतर एवं सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्क विकसित करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोलड़बंद एक्सटेंशन स्थित एमसीडी प्राथमिक विद्यालय के समीप पोटा केबिन परिसर में एमसीडी डिस्पेंसरी शुरू करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्थल की व्यवहार्यता का परीक्षण कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्रवासियों को उनके निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निरीक्षण के दौरान ताजपुर पहाड़ी माइंस एवं मोलड़बंद क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर कूड़ा डाले जाने तथा आवारा पशुओं की समस्या का भी संज्ञान लिया गया। निगमायुक्त ने अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित एवं प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने, जमा कूड़े को तत्काल हटाने तथा आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्ष पश्चिमी जोन में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचीं

नई दिल्ली। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जीएनसीटीडी की अध्यक्ष सुनीता कांगड़ा ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पश्चिमी जोन का दौरा कर सफाई व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सफाई विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विषयों पर अधिकारियों एवं यूनियन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता पश्चिमी जोन के अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय और उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री ने की।

बैठक में सहायक आयुक्त, सफाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सफाई कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, लंबित बकाया, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सेवा संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूनियन प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को आयोग के समक्ष रखा, जिन पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सुनीता कांगड़ा ने पश्चिमी जोन में सफाई व्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जोन में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों और विभिन्न पहलों को अन्य जोन के साथ साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सफल मॉडलों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि सफाई सेवाओं को प्रभावी बनाने और सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े उपायों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए प्रशासन, कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के बीच निरंतर समन्वय जरूरी है। दौरे के दौरान सुनीता कांगड़ा ने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत पश्चिमी जोन परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली में सभी खुदरा शराब की दुकानों को 9 और 10 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया है। सर्कुलर के मुताबिक दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी और मौजूदा हालात को देखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में एल6, एल6 और एल6 एफजी, एल8, एल10 और एल8 और ए14 लाइसेंस के तहत चल रही शराब की सभी खुदरा दुकानों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में पिछले हफ्ते से लगातार विपक्ष दलों के प्रदर्शनों और 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है।

राजघाट पर कांग्रेस का धरना, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में गुरुवार को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर धरना देकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने यह प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग की ओर किए गए मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम' का गायन भी किया और चुनाव प्रक्रिया तथा मताधिकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी।

यादव ने कहा कि कांग्रेस राजघाट इसलिए पहुंची है क्योंकि उसके अनुसार देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की समाधि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग की ओर मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई मोदी-शाह सरकार की कथित तानाशाही को दर्शाती है। यादव ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के अनुरूप नहीं है। देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करोड़ों नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। हालांकि, ये सभी आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए है। यादव ने कहा कि पार्टी मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी आंदोलन करती रहेगी। राजघाट पर आयोजित धरने में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, प्रभारी सचिव दानिश अबरार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जे.पी. अग्रवाल और सुभाष चोपड़ा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ, रमेश कुमार, डॉ. उदित राज, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल, डॉ. योगानंद शास्त्री, प्रदेश महासचिव संगठन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक भीष्म शर्मा, सुरेंद्र कुमार, आसिफ मोहम्मद खान, अब्दुल रहमान, एआईसीसी सचिव अब्दुल हानन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष जगजीवन शर्मा, सीपी मित्तल, कमलकांत शर्मा, मुदित अग्रवाल, अली मेहदी, तस्वीर सोलंकी, लक्ष्मण रावत, महासचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, गौरी शंकर शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, मीर सिंह, धर्मपाल चंदेला, नीतू वर्मा, भूपेश यादव, प्रमोद जयंता, जेपी राणा, विकास शौकीन, जावेद मिर्जा, विनित यादव, बाल किशन बाली, अशोक बसोया, जय प्रकाश समेत कई जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए।

एक नजर

मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

नूंह, एजेंसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2021 के मोबाइल झपटमारी के एक मामले में दोषी आसिफ निवासी गांव शिकारपुर को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर 2021 को अराफात खान निवासी वार्ड नंबर-7, नूंह तावडू रोड स्थित दिल्ली दरबार होटल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल फोन झपट लिया और मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था। पुलिस द्वारा वाहन के संबंध में जानकारी जुटाने पर उसका संबंध गांव टांई निवासी एक व्यक्ति से सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आसिफ का नाम सामने आया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों तथा अन्य साक्ष्यों के माध्यम से आरोपी पर लगे आरोप साबित किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपी आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण के 1038 लंबित मामलों का किया निस्तारण

नूंह। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित विशेष शिविरों में कुल 1038 लंबित मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले में कुल 1,80,088 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 7,961 मामलों में सुनवाई अभी लंबित है। कुल जारी नोटिस के मुकाबले लंबित मामलों का प्रतिशत 4.42 है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा इन मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि नोटिस से संबंधित सुनवाई की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां नोटिस प्राप्त होने के बावजूद संबंधित मतदाताओं ने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से घर-घर सर्वे भी किया जा रहा है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा आवश्यक दस्तावेज संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के दावे एवं आपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया जाएगा।

व्यापारियों के अरबों रुपये एसजीएसटी में अटके: अशोक बुवानीवाला

गुरुग्राम। जीएसटी के टैक्स क्रेडिट सेट-ऑफ के जटिल नियमों के कारण देशभर के लाखों व्यापारियों और उद्यमियों की कार्यशील पूंजी फंस गई है। यह गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने इस व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार से जीएसटी प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने की मांग की है। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के सेट-ऑफ की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह कारोबारियों के लिए नकदी संकट पैदा कर रही है। कारोबारियों के खातों में जमा वैध टैक्स क्रेडिट का समय पर समायोजन या रिफंड नहीं हो पा रहा है। जिससे उनकी पूंजी महीनों तक सरकारी खाते में अटकी रहती है। विस्तार से जानकारी देते हुए अशोक बुवानीवाला ने कहा कि मौजूदा नियम कारोबारियों की नकदी प्रवाह पर सीधा असर डाल रहा है। जब कोई कारोबारी दूसरे राज्य से माल खरीदता है, तो उसे खरीद पर आईजीएसटी चुकाना पड़ता है। बाद में जब वही माल वह अपने राज्य में बेचता है, तो वह ग्राहक से सीजीएसटी और एसजीएसटी वसूलता है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार खरीद पर चुकाए गए आईजीएसटी के क्रेडिट का सेट-ऑफ पहले सीजीएसटी में होता है और सीजीएसटी का कोटा पूरा होने के बाद ही बची हुई राशि का समायोजन एसजीएसटी में किया जाता है। इस क्रम के चलते बड़ी रकम लंबे समय तक एसजीएसटी क्रेडिट के रूप में अटकी रहती है, जबकि कारोबारी को बैंक से कार्यशील पूंजी पर भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देशभर के कारोबारियों के अरबों रुपये इस तरह एसजीएसटी क्रेडिट के रूप में सरकार के पास जमा हैं, लेकिन उसका तत्काल रिफंड या सेट-ऑफ नहीं हो रहा है।

वोट चोरी के आरोप पर गुरुग्राम में भी गरजा विपक्ष

गुरुग्राम, एजेंसी। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने गुरुवार को गुडग़ांव शहर में विशाल विरोध जुलूस निकाला। जुलूस में सेंकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता पानीपत के पूर्व विधायक विरेंद्र पाल शाह ने की।

अपने संबोधन में पानीपत के पूर्व विधायक विरेंद्र पाल शाह ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की चोरी की है। वोट चोरी करके बनाई गई सरकार को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जब तक वोट चोरों को सजा नहीं मिलती, हमारा आंदोलन सडक़ से संसद तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में लोग सरकार के खिलाफ सडक़ों पर है, लेकिन यह सरकार जश्न मनाती फिर रही है। एक व्यक्ति का महिमामंडन किया जा रहा है। गुडग़ांव जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने कहा कि हरियाणा से लेकर देशभर में जिस तरह से चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोटों में हेरफेर किया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ वोट चोरी का पर्दाफाश किया है। गुडग़ांव की जनता इस लूट के खिलाफ सडक़ों पर उतर आई है। महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए यह वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है। इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) वर्धन यादव ने कहा कि यह सरकार जनादेश से नहीं, वोट चोरी से बनी है। ग्रामीण इलाकों में मतदाता सूची से नाम काटे गए और फर्जी वोट जोड़े गए। अगर वोट का अधिकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। सीपीआई-एम से पूर्व राज्य सचिव सुरेंद्र मलिक व जिला सचिव उषा सरोहा ने कहा कि भाजपा सरकार मजदूर, किसान और आम आदमी के वोट के अधिकार पर डाका डाल रही है। सीपीआई-एम नेता ईश्वर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग आज सत्ता पक्ष का मोहरा बन गया है। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि कोमल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने नैतिकता को ताक पर रखा हुआ है। कितने भी घोटाले इस सरकार में हो जाएं, सरकार को शर्म तक नहीं आती।

दुकान में लगी भीषण आग से फटे दो सिलेंडर, महिला और बच्ची की मौत, कई झुलसे

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे के बाजार चौकी क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में दुकान से सटे मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दो गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए। हादसे में एक महिला और पांच वर्षीय बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। धमाकों की आवाज से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, व्यापारी प्रदीप जैन की दुकान में सुबह अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और दुकान से सटे मकान तक पहुंच गईं। आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए। आग और धमाकों से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि आग की चपेट में आने से प्रदीप जैन के बेटे अंकुर जैन समेत कई लोग झुलस गए। वहीं बिंदु प्रसाद जैन समेत दो महिलाएं और दो बच्चे मकान के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में झुलसे लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद बाजार में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आग की लपटों और सिलेंडर धमाकों के चलते काफी देर तक इलाके में दहशत का माहौल रहा। सीओ रोहन चौरसिया ने बताया कि हादसे में 38 वर्षीय स्वाति जैन और पांच वर्षीय आन्या जैन की मौत हुई है।

गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से मजबूत होगी शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था: आरती राव

गुरुग्राम। जिला के गरीबों और वंचितों की अच्छी सेहत का रास्ता अब अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से निकलेगा। यहीं पर इनकी सेहत सुधरेगी। इसके लिए गुरुग्राम जिले में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने, संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैसर्स एएसआर हॉस्पिटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को 26 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपये का कार्य आदेश जारी किया है। इसकी अवधि समझौते की तारीख से दो वर्ष रहेगी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक उसके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसी सोच को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से शहरी गरीब, झुग्गी बस्तियों, कम आय वाले परिवारों और वंचित वर्गों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध होंगी। गुरुग्राम जिले में कुल 30 स्थानों को अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें हीरा नगर, नरसिंहपुर ढाणी, हरि नगर, शक्ति नगर, भीमगढ़ खेड़ी, शिवाजी नगर, अर्जुन नगर, चंदन नगर, समालपुर, सेक्टर-56 घाटा गांव, सेक्टर-55, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-27, गंगा विहार, टिकरी ढाणी, मनोहर नगर, सूर्य विहार, धर्म कॉलोनी, ग्वाल पहाड़ी, प्रेम नगर, सरहौल, राम विहार, तिगरा गांव, सेक्टर-54, सराय गांव और कन्हई सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों का चयन इस प्रकार किया गया है कि बड़ी संख्या में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर स्थित अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े। अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत 12 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व देखभाल, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, संक्रामक रोगों का प्रबंधन, सामान्य बीमारियों की ओपीडी, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं उपचार, आंख व ईएनटी संबंधी सेवाएं, मौखिक स्वास्थ्य, बुजुर्ग एवं पेलिएटिव केयर, आपातकालीन सेवाएं तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच एवं प्रबंधन शामिल हैं।

वायु सेना का 94 वां स्थापना दिवस: हिंडन पर परेड में एयर फोर्स के चीफ ने ली सलामी, प्रदर्शन में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर आज गुरुवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया । स्थापना दिवस समारोह के दौरान 94वें एयरफोर्स डे परेड की शुरुआत हुई, जिसमें वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम व अनुशासन की सराहना की। इसमें परेड से लेकर विमानों की प्रदर्शनी और करतब शामिल हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे से राष्ट्रगान से हुई। जो दोपहर बाद तक चलेगी। इस अवसर पर परिसर में लड़ाकू विमान और हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस, आकाश और ध्रुव भी इस दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल ए के सिंह, नेवी चीफ (नौसेना प्रमुख) एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इस समय एयरफोर्स की महिला बटालियन नीले ड्रेस में ध्वज लेकर निकली है। उनके पीछे बटालियन में शामिल एयरफोर्स कर्मी कदम ताल करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़े। पंडाल में बैठे लोग इस पल को यादगार बनाने में जुटे हैं। वे अपने मोबाइल से तस्वीरें और वीडियो रिकार्ड कर रहे हैं। हाथ हिलाकर एयरफोर्स कर्मियों का जोश बढ़ा रहे हैं। हिंडन स्टेशन पर इस वक्त देश भक्ति का माहौल है। लोग तिरंगा लहरा रहा है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पहले इस कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को भी आना था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका आना टल गया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम को देखते हुए गाजियाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन के 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन उड़ाने पर रोक है। कुछ समय के लिए यातायात भी डायवर्ट किया गया है।

अंतरजातीय विवाह से सामाजिक समरसता को मिल रहा बढ़ावा, नवदंपतियों के लिए संबल बनी सरकारी सहायता

नूंह, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सामने लाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना जिले में सामाजिक सद्भाव, समानता और भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपतियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे नवदंपतियों को वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करने में आर्थिक संबल मिलने के साथ ही समाज में समानता और सामाजिक समरसता का संदेश भी पहुंच रहा है। वर्ष 2017 से 2026 तक जिले में इस योजना के तहत 32 लाभार्थियों को कुल 70 लाख 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2020 से पात्र लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। फिरोजपुर झिरका निवासी रजनी पुत्री गिरराज प्रसाद योजना की लाभार्थी हैं। उन्हें 17 जून 2020 को 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता से उन्हें वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत के दौरान आर्थिक सहारा मिला। सौंख निवासी अशोक कुमार पुत्र सूबे सिंह को भी 17 जून 2020 को योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि मिली। उन्होंने कहा कि योजना आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ समाज में समानता और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने का काम कर रही है। तावडू निवासी शीतल पुत्री जयप्रकाश को 17 जून 2020 को 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि योजना से मिली आर्थिक सहायता ने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत में सहयोग दिया। नूंह निवासी ज्योति पुत्री प्रीतम सिंह को 28 फरवरी 2022 को योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की सहायता मिली। उनका कहना है कि इस प्रकार की सरकारी सहायता सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ पात्र परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक है। राठीवास, तावडू निवासी प्रेमवती को 23 सितंबर 2023 को योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी आर्थिक सहयोग ने उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत को मजबूती देने में मदद की। जिले में योजना के तहत अब तक 32 लाभार्थियों को मिली 70 लाख 3 हजार रुपये की सहायता इस दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयासों को दर्शाती है।

अवैध हथियार सहित पांच गिरफ्तार

नूंह। अपराधियों की धर-पकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नूंह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिरोजपुर झिरका सीआईए स्टाफ की टीम ने थाना सदर नूंह क्षेत्र से एक वांछित आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न थानों में चोरी, गोकशी, आर्म्स एक्ट तथा जानलेवा हमले सहित करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल निवासी पल्ला, थाना सदर नूंह के रूप में हुई है। सीआईए फिरोजपुर झिरका प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना सदर नूंह क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जिला रेवाड़ी के थाना कसौला में दर्ज एक मामले में वांछित आरोपी राहुल अवैध हथियार सहित क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और आरोपी को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर और दो कारतूस बरामद किए गए।

हार्ट अटैक से पहले सीने में दर्द का इंतजार करना हो सकता है जानलेवा

गुरुग्राम। डब्ल्यूएचओ की अक्टूबर 2026 की नई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इस्केमिक हार्ट डिजीज से दुनियाभर में लगभग 95 लाख मौतें हुईं, जो मौत का सबसे बड़ा कारण है। भारत में आईसीएमआर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक कुल मौतों में 28.1 प्रतिशत हिस्सा हार्ट और रक्त वाहिकाओं की बीमारियों का है, जिसमें 80 प्रतिशत योगदान हार्ट अटैक और स्ट्रोक का है। यह अहम जानकारी गुरुवार को यहां लीला होटल में शुरू हुए तीन दिवसीय इको एशिया/इको इंडिया-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई। यह सम्मेलन शेपिंग द न्यू इरा ऑफ कार्डिएक इमेजिंग थीम पर आयोजित किया जा रहा है।

इस सम्मेलन के पहले दिन विशेषज्ञों ने कहा कि हार्ट अटैक से पहले सीने में दर्द का इंतजार करना जानलेवा हो सकता है। हृदय में शुरुआती बदलाव लक्षण दिखने से महीनों-वर्षों पहले ही शुरू हो जाते हैं। बिना लक्षण के भी हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। विशेषज्ञों ने कहा कि कहा कि आधुनिक इमेजिंग और एआई की मदद से छिपी हुई हृदय बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सकता है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि बॉडी बनाने के लिए लोग जिम भी जा रहे हैं। मैराथनों में भी भाग ले रहे हैं। जिम में और मैराथन में भाग लेने के दौरान मौतों की संख्या बढ़ रही है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गनाइजिंग प्रेसिडेंट आईएई डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा हृदय रोग में लक्षणों का इंतजार करना सही तरीका नहीं है। सम्मेलन में स्टेज-बी हार्ट फेल्योर पर विशेष चर्चा हुई। इस स्टेज में मरीज को कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन दिल की बनावट और काम करने के तरीके में बदलाव शुरू हो चुके होते हैं। साइंटिफिक कमेटी आईएई चेयरमैन डॉ. हंसा गुप्ता ने कहा कि इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेन इमेजिंग जैसी जांचें दिल की कार्यक्षमता में हो रहे शुरुआती बदलावों को पहचानने में मदद करती हैं। इंटरनेशनल चेयरमैन डॉ. जे. ओह ने कहा कि कई डायबिटिक मरीजों को सीने में दर्द नहीं होता, लेकिन दिल की मांसपेशियों में बदलाव शुरू हो चुके होते हैं।

फरीदाबाद : एचआर मैनेजर के हत्यारोपी मुठभेड़ के बाद काबू, पैर में लगी गोली

फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में एचआर मैनेजर लक्ष्मण (45) के दो हत्यारोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकडऩे में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पकडऩे के दौरान क्राइम ब्रांच और आरोपियों के बीच में गुरुवार तडक़े मुठभेड़ हुई। जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मौके से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। क्राइम ब्रांच को बुधवार को देर रात सूचना मिली थी कि लक्ष्मण हत्याकांड में वांछित आरोपी सेक्टर-62 स्थित सीवर पाइप के गोदाम में छिपे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने गोदाम की घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही दोनों आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, भागने के दौरान आरोपी तरुण उर्फ नवीन निवासी ऊंचा गांव ने टीम पर दो फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तरुण के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके से काबू कर लिया गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल बरामद की। वहीं, तरुण के साथ मौजूद आरोपी जतिन को भी पुलिस ने सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मण हत्याकांड में क्राइम ब्रांच तीन अन्य आरोपियों प्रशांत, नमन और आकाश को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तरुण और जतिन की गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या पांच हो गई है। गौरतलब है कि चार अक्टूबर की रात शाहपुर निवासी लक्ष्मण अपने भतीजे महेश के साथ केले खरीदने गया था। रिंकू चाट की दुकान चलाने के साथ फल भी बेचता है। लक्ष्मण ने उससे एक दर्जन केले लिए, जिसकी कीमत रिंकू ने 100 रुपए बताई। इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद रिंकू ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि आरोपियों ने लक्ष्मण और उसके भतीजे महेश पर हमला कर दिया। हमले में लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेश घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

नूंह में कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर किया प्रदर्शन

नूंह, एजेंसी। 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। इसी कड़ी में नूंह जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर विशेष रूप से शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से होडल चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शहीदा खान, पीसीसी सदस्य महताब अहमद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हाजी इब्राहिम इंजीनियर बिसरू, अंजुम पूर्व पार्षद, इरशाद अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में अशोक तंवर ने आरोप लगाया कि पिछले करीब ढाई वर्षों के दौरान एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर 13 से 14 करोड़ मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के समर्थन में नहीं रहने वाले मतदाताओं को कथित रूप से चुनाव आयोग से मिलीभगत कर चिन्हित किया जा रहा है और उनके वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब मीडिया ने भी इस मामले को सामने लाने का काम किया है। राहुल गांधी द्वारा जंतर-मंतर और संसद पर प्रदर्शन कर चुनाव आयोग का घेराव किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने की है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को मताधिकार का अधिकार दिया है। यदि नागरिकों का वोट देने का अधिकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश का सामाजिक ताना-बाना कैसे मजबूत रहेगा।

प्रदर्शनकारियों के मन से खत्म हो रहा दिल्ली पुलिस का डर

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें केवल प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने-सामने नहीं हैं। उनके बीच अब मोबाइल कैमरा भी खड़ा है, सोशल मीडिया भी खड़ा है और कुछ सेकंड में किसी घटना को देशभर में पहुंचा देने वाली तकनीक भी खड़ी है। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस के लिए आज किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करना केवल बैरिकेड लगाने, भीड़ को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का मामला नहीं रह गया है। पुलिस को कानून लागू भी करना है, स्वयं को उकसावे से बचाना भी है और साथ-साथ यह सुनिश्चित भी करना है कि अगले कुछ सेकंड में उसकी कोई प्रतिक्रिया काट-छांटकर वायरल वीडियो न बन जाए। दो अक्टूबर से नई दिल्ली क्षेत्र में शुरू हुए प्रदर्शनों ने कुछ ही दिनों में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अलग-अलग राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, कार्यकर्ताओं और दूसरे समूहों के प्रदर्शन तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की कोशिशों के कारण पुलिस को लगातार अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। केवल एक स्थान पर खड़ी भीड़ के बजाय अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ते समूहों को संभालना पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक असहज सवाल भी उठता है।

सवाल यह है कि क्या जुलाई में जंतर-मंतर के प्रदर्शन से जुड़े मामलों में प्राथमिकी निरस्त किए जाने के चलते ही प्रदर्शनकारियों के बीच यह संदेश गया कि पुलिस के साथ टकराव का कानूनी परिणाम गंभीर नहीं होगा? क्या इसी कारण प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस का डर कम हो गया है? क्या इसी कारण कुछ लोग अब पुलिसकर्मियों से आक्रामक भाषा में बात करने, उन्हें चुनौती देने, धक्का-मुक्की करने या जानबूझकर उकसाने का जोखिम अधिक आसानी से उठा रहे हैं? हम आपको याद दिला दें कि जुलाई में हुए प्रदर्शनों के बाद दिल्ली पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकियों को निरस्त कर दिया था। साथ ही अदालती आदेश में यह भी कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में केवल भागीदारी अपने आप में अपराध नहीं मानी जा सकती। ऐसे में जब महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और शारीरिक खींचतान के मामले सामने आ रहे हैं और पुरुष पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार के झूठे आरोप तक लगाये जा रहे हैं तब यह सवाल प्रमुखता से उठता है कि क्या एफआईआर निरस्त कर प्रदर्शनकारियों को सुधरने का जो मौका दिया गया था उसका उन्होंने गलत फायदा उठाया? दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस भी आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में तकनीक के सहारे अपना बचाव कर रही है। नई दिल्ली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की वर्दी पर बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं। संसद मार्ग पर प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयार पुलिसकर्मियों की वर्दी पर ये छोटे कैमरे साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की रणनीति में सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बढ़ाया गया है और कई पुलिसकर्मी डंडों के बिना तैनात दिखाई दिए। देखा जाये तो बॉडीकैम का अर्थ केवल पुलिस को आरोपों से बचाना नहीं है। यदि कोई पुलिसकर्मी सीमा पार करता है तो वही कैमरा उसके खिलाफ भी प्रमाण बन सकता है। यदि कोई प्रदर्शनकारी पुलिस को जानबूझकर उकसाता है, बैरिकेड तोड़ता है, हमला करता है या बाद में घटनाक्रम का अधूरा वीडियो प्रस्तुत करता है तो पुलिस के पास पूरी घटना का अपना दृश्य रिकॉर्ड मौजूद रहेगा।

इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था में दूसरा बड़ा परिवर्तन बहुस्तरीय बैरिकेडिंग है। प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तरों पर अवरोध लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। ताजा प्रदर्शनों से पहले उन स्थानों तक की पहचान की गई जहाँ टूटा हुआ फुटपाथ, पत्थर अथवा दीवार का हिस्सा तनाव बढ़ने पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जुलाई के अनुभवों के बाद सुरक्षा व्यवस्था की इस तरह समीक्षा बताती है कि अब भीड़ प्रबंधन में केवल पुलिस बल की संख्या नहीं, बल्कि प्रदर्शन-स्थल के भौतिक वातावरण को भी सुरक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। एक और समस्या सोशल मीडिया की है। पुलिसकर्मी के चेहरे के बिल्कुल सामने कैमरा रख देना, लगातार सवाल करना, नारे लगाना अथवा ऐसी परिस्थिति बनाना जिसमें उससे कोई तीखी प्रतिक्रिया निकल जाए, ऐसे माहौल में पुलिसकर्मी के कुछ सेकंड के नियंत्रण खोने का परिणाम लाखों लोगों तक पहुंचने वाला वीडियो हो सकता है। इसीलिए नई पुलिस रणनीति में आत्मसंयम स्वयं एक सुरक्षा उपकरण बन गया है। इस चुनौती की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब तकनीक के जरिये फर्जी दृश्य भी बनाए जाने लगें। दिल्ली पुलिस ने हाल में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एआई की मदद से ऐसा वीडियो बनाया जिसमें एक पुलिसकर्मी को महिला के साथ दुर्व्यवहार करते दिखाया गया था। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस के सामने इस समय बेहद कठिन चुनौती है। उसे प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करनी है। उसे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करनी है। अपने जवानों विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा करनी है। उसे आरोप लगने पर जवाबदेह भी होना है। साथ ही बैरिकेड टूटने, प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ घुसने अथवा हिंसा होने की स्थिति में कानून भी लागू करना है। शायद इसीलिए राजधानी की पुलिसिंग तेजी से बदल रही है। वर्दी पर बॉडीकैम, बहुस्तरीय बैरिकेड, लाउडस्पीकर से लगातार चेतावनी और सूचना, अतिरिक्त पुलिस तथा अर्धसैनिक बल, संवेदनशील रास्तों की पहले से पहचान, मोबाइल वीडियो के समानांतर पुलिस की अपनी रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर फैलने वाली संदिग्ध सामग्री की डिजिटल जांच। लेकिन तकनीक चाहे जितनी बढ़ जाए, अंततः सबसे बड़ी परीक्षा सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी के धैर्य की ही है। जनता भी पुलिस की दिक्कतों को समझ रही है और उसका हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर रही है।

नाना की विशेषता थी कि उनके अभिनय में बनावट नहीं थी। वे पारंपरिक नायक की छवि में फिट नहीं बैठते थे। न चमकदार चेहरा। न बनावटी मुस्कान। न नायक बनने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अदाएँ लेकिन जब पर्दे पर आते थे तो दूसरे कलाकारों की उपस्थिति छोटी पड़ जाती थी। फिल्म परिंदा में उनका भयावह व्यक्तित्व देखिए। फिल्म प्रहार में अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण देखिए। फिल्म क्रांतिवीर में व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह देखिए। फिल्म यशवंत में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का आक्रोश देखिए। फिल्म ‘अब तक छप्पन’ में कठोरता देखिए। और फिर फिल्म ‘वेलकम’ में उनकी अद्भुत हास्य प्रतिभा देखिए। एक ही अभिनेता के इतने रूप! यही नाना की विलक्षणता थी। उनकी फिल्म क्रांतिवीर का वह दृश्य भला कौन भूल सकता है, जब वे फाँसी के तख्ते पर खड़े होकर गरजते हैं,- ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने! ‘यह केवल एक फिल्मी संवाद नहीं था। यह उस व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश था। जिसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति ही अपराधी बना दिया जाता है। इसी फिल्म में उनका एक और संवाद समाज की सांप्रदायिक संकीर्णता पर सीधा प्रहार करता है,- ‘बता ये मुसलमान का खून है या ये हिंदू का खून है, बता! ‘नाना के संवादों में मनोरंजन के साथ सामाजिक चेतना भी थी। वे दर्शकों को उत्तेजित ही नहीं करते थे। सोचने के लिए भी विवश करते थे। फिल्म यशवंत का उनका प्रसिद्ध मच्छर वाला संवाद आज भी लोगों की जुबान पर है।

स्मृति शेष: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर

के. के. उपाध्याय

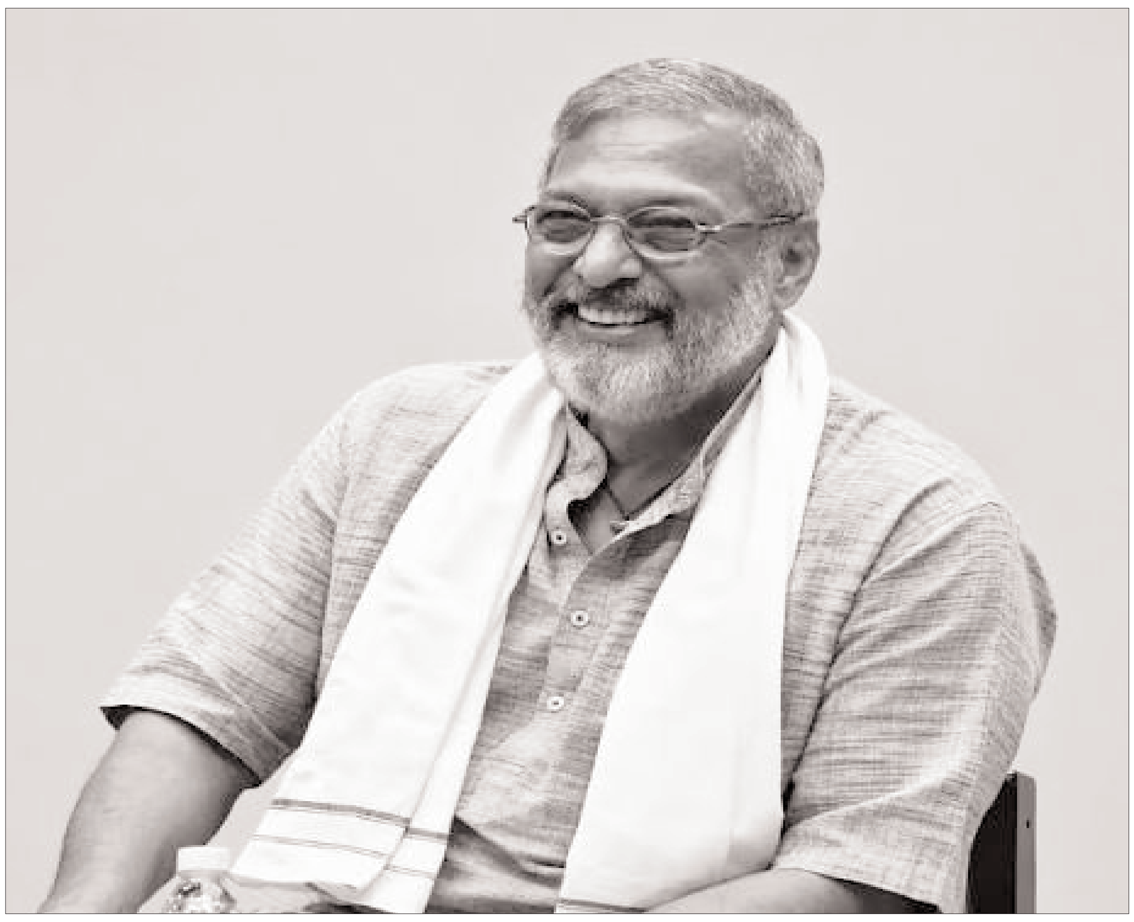

नाना पाटेकर का दुनिया से चले जाना अभिनय जगत में ऐसा शून्य छोड़ गया है, जिसके समकक्ष पहुंच पाना बहुत कठिन होगा। कुछ अभिनेता उभरकर सिने पर्दे पर आते हैं, उनका अभिनय आकर्षित करता है तो तालियां बटोरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार दर्शकों के दिल में गहरे तक उतर जाते हैं। उनके फिल्मी संवाद स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं। उनका चेहरा एक विचार बन जाता है। उनकी आवाज़ व्यवस्था से सवाल पूछने लगती है। नाना पाटेकर ऐसे ही कलाकार थे। वे सिर्फ अभिनेता नहीं थे, शानदार इंसान भी थे। बेबाक। संवेदनशील। स्वाभिमानी। अपनी शर्तों पर जीने वाले। अभिनय में जितने प्रखर, निजी जीवन में उतने ही सादगी प्रिय। नाना को देखकर कभी लगा ही नहीं कि वे अभिनय कर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे पर्दे से सीधे दर्शकों के साथ संवाद कर रहे हों। उनकी आँखें बोलती थीं। चेहरे की एक-एक रेखा संवाद करती थी। आवाज़ में अद्भुत दम था। संवाद अदायगी में ऐसा प्रवाह कि शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। वे संवाद बोलते नहीं थे, उन्हें जीते थे। मुझे आज भी याद है। मैंने नाना पाटेकर की पहली फिल्म प्रतिघात देखी थी। वह 1987 का दौर था। उस फिल्म में उनका किरदार मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई देता था लेकिन उसकी बातें देश की थीं। व्यवस्था की थीं। समाज की थीं। उसकी बेचैनी में एक सामान्य नागरिक का आक्रोश था। वह किरदार मेरे मन में कहीं ठहर गया। उस समय शायद कल्पना भी नहीं की थी कि यही अभिनेता आगे चलकर भारतीय सिनेमा में अभिनय की अलग परिभाषा लिखेगा। नाना की विशेषता थी कि उनके अभिनय में बनावट नहीं थी। वे पारंपरिक नायक की छवि में फिट नहीं बैठते थे। न चमकदार चेहरा। न बनावटी मुस्कान। न नायक बनने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अदाएँ लेकिन जब पर्दे पर आते थे तो दूसरे कलाकारों की उपस्थिति छोटी पड़ जाती थी। फिल्म

परिंदा में उनका भयावह व्यक्तित्व देखिए। फिल्म प्रहार में अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण देखिए। फिल्म क्रांतिवीर में व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह देखिए। फिल्म यशवंत में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का आक्रोश देखिए। फिल्म ‘अब तक छप्पन’ में कठोरता देखिए। और फिर फिल्म ‘वेलकम’ में उनकी अद्भुत हास्य प्रतिभा देखिए। एक ही अभिनेता के इतने रूप! यही नाना की विलक्षणता थी। उनकी फिल्म क्रांतिवीर का वह दृश्य भला कौन भूल सकता है, जब वे फाँसी के तख्ते पर खड़े होकर गरजते हैं,- ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने! ‘यह केवल एक फिल्मी संवाद नहीं था। यह उस व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश था। जिसमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति ही अपराधी बना दिया जाता है। इसी फिल्म में उनका एक और संवाद समाज की सांप्रदायिक संकीर्णता पर सीधा प्रहार करता है,- ‘बता ये मुसलमान का खून है या ये हिंदू का खून है, बता! ‘नाना के संवादों में मनोरंजन के साथ सामाजिक चेतना भी थी। वे दर्शकों को उत्तेजित ही नहीं करते थे। सोचने के लिए भी विवश करते थे। फिल्म यशवंत का उनका प्रसिद्ध मच्छर वाला संवाद आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। फिल्म तिरंगा का वह अंदाज़ ‘पहले लात, फिर बात... ‘आज भी याद किया जाता है। और फिल्म वेलकम में उदय शेट्टी बनकर उनका यह कहना कि ‘भगवान का दिया हुआ सबकुछ है...’ हास्य अभिनय की यादगार मिसाल बन गया। सोचिए! जिस अभिनेता की आवाज़ सुनकर दर्शकों की मुट्ठियाँ तन जाती थीं, वही अभिनेता कुछ वर्षों बाद अपनी अदाओं से उन्हें ठहाके लगाने पर मजबूर कर देता था।

यह साधारण प्रतिभा नहीं थी। लेकिन नाना के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी था। जो संभवत: उनके अभिनय से कहीं अधिक बड़ा था। महाराष्ट्र में जब किसान सूखे और आत्महत्या की त्रासदी से जूझ रहे थे, तब नाना केवल संवेदना व्यक्त करके नहीं रह गए। उन्होंने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर साल 2015 में ‘नाम फाउंडेशन’ की शुरुआत की। किसान परिवारों की सहायता, जल संरक्षण और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। यही अंतर है प्रसिद्धि और सार्थकता में। बहुत से लोग फिल्मों में किसानों का दर्द बेचते हैं। नाना किसानों का दर्द बाँटने उनके बीच पहुँचते थे। उनके जीवन में देश के प्रति लगाव केवल संवादों तक सीमित नहीं था। फिल्म प्रहार के लिए उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लिया। भारतीय प्रादेशिक सेना से उनका जुड़ाव रहा। उनके भीतर सैनिक अनुशासन और देश के प्रति सम्मान का भाव स्पष्ट दिखाई देता था। तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान उनकी प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थे। लेकिन नाना की असली उपलब्धि पुरस्कार नहीं थे। वह स्थान था, जो उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदय में बनाया। नाना पाटेकर की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे असहज करने वाले सवाल पूछने से नहीं डरते थे। उनके अभिनय में विद्रोह था लेकिन वह निरर्थक विद्रोह नहीं था। उसमें समाज के प्रति चिंता थी। व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। अन्याय के प्रति असहमति थी। आज सिनेमा में तकनीक बढ़ गई है। दृश्य भव्य हो गए हैं। प्रचार का शोर बढ़ गया है लेकिन ऐसे कलाकार कम होते जा रहे हैं, जो केवल अपनी आवाज़, आँखों और चेहरे के भावों से पूरा दृश्य अपने नाम कर लें। नाना ऐसे ही कलाकार थे। आज उनके निधन का समाचार आया तो मन अचानक फिल्म ‘प्रतिघात’ के उस किरदार की ओर लौट गया, जिसे मैंने लगभग चार दशक पहले देखा था। तब वह किरदार देश और व्यवस्था से सवाल पूछ रहा था। बाद के दशकों में नाना ने अलग-अलग किरदारों के माध्यम से वही बेचैनी जीवित रखी। नाना चले गए। लेकिन उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। उनका आक्रोश नहीं जाएगा। उनके संवाद नहीं जाएँगे। उनका वह विशिष्ट अंदाज़ नहीं जाएगा। जब भी भारतीय सिनेमा में स्वाभाविक अभिनय की चर्चा होगी, जब भी दमदार संवाद अदायगी का उल्लेख होगा, जब भी पर्दे पर व्यवस्था से टकराने वाले किसी विद्रोही चरित्र की बात होगी, नाना पाटेकर याद आएँगे। क्योंकि नाना पाटेकर केवल किरदार नहीं निभाते थे। वे किरदारों में अपना जीवन भर देते थे। ऐसे कलाकार मरते नहीं। वे अपने अभिनय में जीवित रहते हैं। अलविदा नाना! आपके जाने से पर्दा सूना हुआ है। लेकिन आपकी आवाज़ और अदायगी भारतीय सिनेमा की स्मृतियों में हमेशा गूँजती रहेगी।

विनम्र श्रद्धांजलि।

विचार

दवा में डकैती

प्रमोद भार्गव

सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं की एमआरपी और सरकारी खरीद मूल्य के बीच बड़े अंतर को अजूबा करार दिया है। यह अंतर 10 गुना से भी ज्यादा है। 2700 रुपए की खुदरा बिक्री वाली कैंसर की दवा पर एमआरपी 27,000 रुपए अंकित होने पर इसे न्यायामूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने पहले तो ‘दिनदहाड़े’ डकैती कहा और फिर 29 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई में इस भारी अंतर को दो टूक शब्दों में ‘कत्लेआम’ यानी ‘सामूहिक संहार’ तक कहने में संकोच नहीं किया। दवा कारोबारी, निजी और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद करने वाले जिम्मेदारों के लिए इससे तीखी टिप्पणी, दूसरी कोई हो नहीं सकती। अदालत ने यह सवाल भी खड़ा किया कि ‘इतना पैसा कहां जा रहा है और फायदा किसे हो रहा है?’ यह टिप्पणी सीधे-सीधे दवा उत्पादक, निजी अस्पतालों के मालिक एवं चिकित्सक तथा सरकारी खरीद में लिप्त जिम्मेवारों का अमानवीय चेहरा सामने लाती है। यह विडंबना तब है, जब भारत सरकार एक दवा, एक मूल्य और एक गुणवत्ता नीति से जुड़ा कानून फरवरी 2025 में पूरे देश में लागू कर चुकी है। इस नियम के तहत थोक दवा विक्रेताओं और ई-फार्मेसी को दवाओं की मूल्य-सूची को सार्वजनिक रूप से दिखाना अनिवार्य है, ताकि रोगियों को तय दामों पर ही उचित गुणवत्ता की मानक दवाएं मिल सकें। परंतु शीर्ष न्यायालय की इस तीखी प्रतिक्रिया से साफ है कि दवा विक्रेताओं और सरकारी दवा खरीद से जुड़े अधिकारियों ने इस कानून को बट्टे खाते में डाल दिया है। कॉरपोरेट अस्पताल अब सेवा नहीं उद्योग बन गए हैं। यहां तक कि ये अस्पताल के भीतर स्थित मेडिकल स्टोर से ही रोगी को दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यदि कोई रोगी बाहर से दवा लाने को कहता है तो उपचार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने की बात (एक तरह की धमकी) कहते हैं। जबकि इनमें से ज्यादातर अस्पताल आयुष्मान भारत और अन्य सरकारी लाभदायी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी उपचार करते हैं। यानी दवा उत्पादकों और अस्पतालों की मनमानी कानून अस्तित्व में आने के बाद भी बनी हुई है।

फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर करती हैं, यह भी बड़ा सवाल है ? साफ है, जब दवाएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती हैं तो फिर एमआरपी के छद्म आधारित मूल्य व्यवस्था कैसे और क्यों बनी हुई है? जबकि सबका स्वस्थ रहना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। कुछ समय पहले कंपनी मामलों के मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट ने सरकार को आगाह किया गया था कि दवाएं आम आदमी की पहुंच से जानबूझकर बाहर की जा रही हैं। इस रिपोर्ट ने तय किया कि दवाओं की महंगाई का कारण दवा में लगने वाली सामग्री का महंगा होना नहीं है बल्कि दवा कंपनियों के मुनाफे की हवस में बदल जाना है। इस लालच के चलते कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के नियमों का भी पालन नहीं करती हैं और दवाओं की कीमत कई सैकड़ा गुना तक अधिक रख देती हैं। यहां तक कि नामीगिरामी दवा कंपनियां भी दो सौ से पांच सौ गुना ज्यादा कीमत अपने दवा उत्पादों की रख रही हैं। ये महंगे दवा उत्पाद सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के बूते खपाए जाते हैं। इसके पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी देशी-विदेशी दवा कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दवा कंपनियों ने सरकार द्वारा दी उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ तो लिया लेकिन दवाओं की कीमतों में कटौती नहीं की। यह गोलमाल प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के साथ तो हो ही रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ राजस्व कर के रूप में भी हो रहा है। इस धोखाधड़ी को लेकर सीएजी ने सरकार को दवा मूल्य नियंत्रण अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया था। ऐसे ही सुझावों को मानते हुए सरकार ने देशभर में फैले सीजीएचएस के 1200 अस्पताल, 200 जांच केंद्र, 500 वेलनेस सेंटर और 8000 से अधिक जन-औषधि भंडारों पर एक मूल्य, एक दवा भेजने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। हालांकि इस योजना पर प्रभावी अमल की दृष्टि से सरकार को मजबूत और पारदर्शी नेटवर्क बनाना होगा। जिसके लिए प्रभावी डेटा भी जरूरी है। इस दवा वितरण में बोली के आधार पर भागीदारी करने वाले विक्रेताओं की तकनीकी योग्यता से कहीं ज्यादा ईमानदारी के मानदंडों की जरूरत है। दवा क्रय समिति को भी उन दवाओं को खरीदने की जरूरत है, जो उपचार में प्रभावी और कीमत में सस्ती हों। क्योंकि अंततः सरकार का उद्देश्य आम आदमी को सस्ती, असरकारी और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना ही है। चूंकि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए उन्हें भी यदि इस योजना में भागीदार बना लिया जाए तो दवा वितरण का दायरा तो बढ़ा होगा ही, लाभ लेने वाले रोगियों का दायरा भी बढ़ जाएगा। इंसान की जीवन-रक्षा से जुड़ा दवा करोबार अपने देश में तेजी से मुनाफे की अमानवीय व अनैतिक हवस में बदलता जा रहा है। चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर रोगियों के लिए महंगी और गैर जरुरी दवाएं लिखवाने का प्रचलन लाभ का धंधा हो गया है। बेमतलब की अनेक जांचें केवल मुनाफे के लिए कराई जा रही हैं।

एक नजर

भागलपुर में पीएनजी सप्लाई की कवायद तेज : आईओसीएल ने शुरू किया घरेलू सर्वे, जनता से लिया जा रहा फीडबैक

भागलपुर। शहर के घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भागलपुर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य पाइप से गैस सप्लाई को लेकर आम जनता की रुचि जानना और उनका फीडबैक इकट्ठा करना है। सर्वे के दौरान आईओसीएल के अधिकारी और टीम सीधे निवासियों से संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से क्या स्थानीय निवासी अपने घरों में पारंपरिक सिलेंडर के बजाय पाइप्ड गैस अपनाने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र के हिसाब से संभावित उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है और वहां गैस की दैनिक मांग कितनी हो सकती है, इसका सटीक डेटा तैयार किया जा रहा है आदि जानकारी एकत्रित की जा रही है। कंपनी के अनुसार, किसी भी नए क्षेत्र में गैस पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा तैयार करने से पहले सर्वे करना एक अनिवार्य और तकनीकी शर्त है। पाइपलाइन बिछाने में भारी निवेश और समय लगता है, इसलिए काम शुरू करने से पहले उस विशिष्ट इलाके में संभावित यूजर्स की संख्या और गैस की वास्तविक मांग का सही अनुमान लगाना बेहद जरूरी होता है। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईओसीएल की टीम एकत्रित किए गए सभी डेटा का गहन विश्लेषण करेगी। आईओसीएल के भौगोलिक क्षेत्र प्रभारी विकास टोला ने सर्वे चलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस सर्वे के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। भागलपुर के किन इलाकों में और कब गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसका अंतिम फैसला पूरी तरह से इस सर्वे से प्राप्त रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही लिया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के 5 ठिकानों पर इओयू की छापेमारी

भागलपुर। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईओयू की टीमों ने एक साथ भागलपुर सहित 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद आज सुबह ही ईओयू की अलग-अलग टीमों ने अभियंता के ठिकानों पर एक साथ दस्तक दी। भागलपुर में तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हनुमान पथ स्थित आलीशान पैतृक आवास है जहां छापामारी चल रही है। इसके अलावा मुंगेर बेलन बाजार, बंगाली टोला स्थित मकान, मुंगेर कार्यालय, मुजफ्फरपुर और पटना में छापामारी जारी है। शुरुआती कार्रवाई में ही मुजफ्फरपुर स्थित 'राधिका अपार्टमेंट' के फ्लैट से 50 लाख रुपये कैश (नकद) बरामद होने की खबर है, जिसके बाद नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नारद कुमार दास के खिलाफ बुधवार को ही ईओयू थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिक जांच में उनके पास वैध आय से करीब 64.93% अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं, जो उनकी ज्ञात कानूनी आय से 83 लाख से भी ज्यादा है। फिलहाल सभी ठिकानों पर छापेमारी जारी है। टीम उनके बैंक खातों, लॉकर, जमीन-जायदाद के कागजातों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। अधिकारियों का मानना है कि पूरी जांच के बाद काली कमाई का यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। इस अचानक हुई कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

हत्या कर झाड़ी में फेंका मिला किसान का शव, गांव में सनसनी

नवादा। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के भट्ट गांव में किसान भरत चौधरी की हत्या कर शव झाड़ी में फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को झाड़ी से शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार, भरत चौधरी बुधवार की शाम खेत में पटवन करने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन को चिंता हुई। इसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अंततः मृतक की पत्नी सुशीला देवी ने काशीचक थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी बीच गुरुवार को ग्रामीणों की नजर झाड़ी में फेंके गए एक शव पर पड़ी। इसकी सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान भरत चौधरी के रूप में की। शव पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका गहरा गई। मृतक के दाहिने पैर में गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। साक्ष्य जुटाने और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया है। टीम घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की मदद करेगी। इस संबंध में नवादा की पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

एक करोड़ परिवारों को उद्यमी परिवार बनाना है : सम्राट चौधरी

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बापू सभागार में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त की राशि के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के 1 करोड़ परिवारों को उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी परिवार बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के बिहार को समृद्ध बनाने के सपने और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अगले पांच वर्षों में राज्य में उद्योग, रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, इसमें कम से कम दसवां हिस्सा बिहार को मिलने की संभावना है। इससे राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एमएसएमई के माध्यम से 45,000 उद्यमी तैयार किये जा रहे हैं। इसमें 14 हजार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 10 हजार अतिपिछड़ा, 9 हजार 500 महिला, 9 हजार युवा एवं 2500 अल्पसंख्यक उद्यमी हैं। इसके लिये 3 हजार 500 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार खर्च कर रही है। आज के कार्यक्रम में 7,000 लाभुकों को किस्त की राशि अंतरित की गई। साथ ही प्रत्येक जिले में एमएसएमई केंद्र खोले गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में 700 स्थानों पर सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) खोले गए हैं। यहां विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा मिलेगी। 'विद्यार्थी साथी' ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को 24म7 ऑनलाइन ट्यूटर की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी देर रात तक भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा के प्रति उनकी बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में 211 डिग्री कॉलेज खोले जा चुके हैं। अगले वर्ष से इन कॉलेजों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्रचेज प्रीफ्रेंस एक्ट के तहत बिहार में निर्मित वस्तुओं की 25 से 40 प्रतिशत तक सरकारी खरीद की जायेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड में 5 लाख करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले पांच वर्षों में उद्योगों के लिए 20,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य के 20 महत्वपूर्ण स्थानों पर रोप-वे निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा।

जेपी के संघर्ष और सम्पूर्ण क्रांति के संदेश को आत्मसात करने की जरूरत : संजय सरावगी

पटना। भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक एवं 'सम्पूर्ण क्रांति' के प्रणेता, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में शामिल होकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। संजय सरावगी ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण जीवन राष्ट्र, लोकतंत्र और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए समर्पित रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष तक उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों से देश को नई दिशा देने का कार्य किया। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, सादगी और जनसेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने सत्ता को लक्ष्य नहीं, बल्कि जनसेवा को राजनीति का माध्यम माना। उन्होंने अन्याय, भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाते हुए देश के युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 'सम्पूर्ण क्रांति' का उनका आह्वान केवल राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन की व्यापक परिकल्पना थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हैं। लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष, विचार और आदर्शों से परिचित कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को जेपी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकनायक का जीवन देशवासियों को यह संदेश देता है कि जब लोकतांत्रिक मूल्यों और जन अधिकारों पर संकट आए, तब समाज के प्रत्येक वर्ग को सजग होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उनके विचार और आदर्श सदैव देश और समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी।

माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, अवैध संपत्ति होगी राजसात

किशनगंज। पुलिस सभागार में सितंबर माह की अपराध गोष्ठी एवं पुलिस सभा का आयोजन पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और विधि-व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्षों, अंचल पुलिस निरीक्षकों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। एसपी ने शराब, लॉटरी, मानव तस्करी, पशु, ड्रग्स, बालू, भू-माफिया और इंट्री माफिया समेत सभी प्रकार के संगठित अपराध को जड़ से समाप्त करने का निर्देश दिया। संगठित अपराधियों को चिह्नित कर उनकी अवैध स्रोत से अर्जित संपत्ति के राजसात के लिए BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया। अनुसंधान में गलत जांच रिपोर्ट देकर अभियोजन को कमजोर करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध साक्ष्य सहित रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस दीदी को श्वत्र्स्र डायल-112 से जोड़ने तथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, गर्ल्स हॉस्टल और अन्य हॉटस्पॉट पर जनसंवाद व जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। सभी थानों में शांति समिति का पुनर्गठन कर जनप्रतिनिधियों, युवाओं, व्यवसायियों और अन्य सहयोगी नागरिकों को शामिल करने का निर्देश दिया गया।

नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को सक्रिय रखते हुए अभियान तेज करने और नशामुक्ति के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। किशनगंज और बहादुरगंज थाना क्षेत्रों में चोरी व गृहभेदन के मामलों के शीघ्र उद्भेदन के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया। आगामी दुर्गापूजा, दीपावली, कालीपूजा और छठ पर्व को देखते हुए पुलिस को लगातार निगरानी, निरोधात्मक कार्रवाई तथा भूमि विवाद और साम्प्रदायिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। प्रभावी गश्ती, बीट व सेक्टर पुलिसिंग, गुड मॉर्निंग वॉक तथा विवादित भूमि की सूची तैयार कर निगरानी का भी निर्देश दिया गया। अपराधियों को सजा दिलाने में बेहतर कार्य के लिए जिला अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार और विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह को पुरस्कृत किया गया।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के द्वारा किया गया राजभवन मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

पटना,एजेंसी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में शहीद स्मारक से राजभवन तक निकले मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। जिन्हें अलग-अलग थानों में रखा गया।

मार्च को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को हटाए बिना लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बहाल नहीं हो सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना ही होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के वोट और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ रही है। वोट चोरों को गद्दी से हटाकर ही दम लेंगे। जनता के वोट पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजेश राम ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने से लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से लेकर हर लोकतांत्रिक मंच तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा हम जनता के अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ कांग्रेस की आवाज दबने वाली नहीं है। देशद्रोहियों और गद्दारों के खिलाफ हमारी लड़ाई

रुकने वाली नहीं है। मार्च में अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव, डॉ शकील अहमद खान, पूर्व विधान पार्षद प्रेमचन्द्र मिश्रा, डा समीर कुमार सिंह, मीडिया चेयरमैन डा अजय कुमार पासवान, विधायक मनोज विश्वास, पूर्व विधायक विजय शंकर दूबे, बंटी चौधरी, इजहारूल हुसैन, मुन्ना तिवारी, ऋषि मिश्रा, आनन्द शंकर, मीडिया संयोजक असितनाथ तिवारी, ब्रजेश पाण्डेय, पंकज यादव, मिन्नत रहमानी, ज्ञान रंजन, डा संजय यादव, डा कुमारी सोनी, कमल कमलेश, वैद्यनाथ शर्मा, कुमार आशीष, प्रेमचन्द सिंह, अफरोज खान, अमित कुमार, उमैर खान, सुधीर शर्मा , शशि भूषण पंडित, मंजीत आनन्द साहू, शशांत शेखर, मुकुल यादव, सत्येन्द्र कुमार सिंह, रीता सिंह, हसीब अनवर, विनीता भगत, उदय शंकर पटेल, नदीम अख्तर अंसारी, विमलेश तिवारी, ,निधि पाण्डेय, पूनम यादव, कुमारी अनिता, मेनका कुमारी, रोहित कुमार पासवान, असदुल्लाह, आशुतोष शर्मा, चंदन सिंह, रंजीत कुमार बाल्मीकि , राहुल भारद्वाज, दुर्गा प्रसाद अबरार रजा, डा परवेज, शिवम राज, सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पूर्व कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के 5 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, 83.53 लाख की आय से अधिक संपत्ति का मामला

मुजफ्फरपुर,एजेंसी। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू की टीम ने आज, 8 अक्टूबर 2026 को उनके 5 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों द्वारा की जा रही है।

आर्थिक अपराध इकाई (आर्थिक अपराध प्रभाग), बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी डिटेल के अनुसार, नारद कुमार दास के खिलाफ कांड संख्या-28/26, दिनांक 07.10.2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ईओयू ने विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर आज सुबह ही छापेमारी शुरू कर दी।

आय से 64.93% अधिक संपत्ति का मिला साक्ष्य

प्राथमिक जांच और विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर, अभियुक्त नारद कुमार दास के पास उनके वैध आय स्रोतों की तुलना में कुल 83,53,200 रुपये (तिरासी लाख तिरपन हजार दो सौ रुपये) की अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया है। यह उनकी ज्ञात कानूनी आय से लगभग 64.93 प्रतिशत अधिक है। आरोपी मूल रूप से हनुमान पथ, तिलकामांझी, जिला भागलपुर के निवासी हैं और मुंगेर में पदस्थापित रहे हैं।

इन 5 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी:

1. हनुमान पथ, तिलकामांझी, भागलपुर स्थित पैतृक आवास।
2. बेलन बाजार, बंगाली टोला, थाना-कासिम बाजार, मुंगेर स्थित आवास।
3. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, मुंगेर स्थित सरकारी कार्यालय।
4. फ्लैट नंबर 02स्न, राधिका अपार्टमेंट, नया टोला, काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफ्फरपुर।
5. कुसुमपुरम मोहल्ला, थाना-रुपसपुर, जिला पटना स्थित आवास।

बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इन सभी पांचों स्थानों पर अलग-अलग टीमें गहनता से जांच कर रही हैं। तलाशी की यह कार्रवाई पूरी होने के बाद ईओयू द्वारा इस मामले में विस्तृत विवरण और जब्त किए गए दस्तावेजों या संपत्तियों की अंतिम सूची साझा की जाएगी। इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

अपनी जमीन बचाने करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करें किसान: टिकैत

नवादा। नवादा जिले के मोतनाजे तथा मधुबन गांव में किसानों के सैकड़ो एकड़ भूमि छीनने के विरोध में गुरुवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया ।जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गिरियक से स्वयं ट्रैक्टर चलाकर जुलूस का नेतृत्व किया और सभा स्थल पर पहुंचे ।मंच पर हल और पालो के साथ किसानों ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया।

किसान नेता दिनेश कुमार,अशोक प्रसाद सिंह एवं पुर्व विधायक मो कामरान जी को अंगवस्त्र और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। महापंचायत का उद्घाटन करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम मदद को तैयार है ।यहां न तो लाठीचार्ज हुआ,ना ही आंसूगैस का गोला फूटा तो फिर क्या आप ने दान में जमीन दे दी? उन्होंने जिला प्रशासन को सचेत किया कि सरकारी दमन का किसान मुंह तोड़ जबाव देंगे। मोतनाजे और मधुबन में गंगा जलाशय और टूरिस्ट प्लेस बनाने के नाम पर सैकड़ों वर्षो से बसे गाँवों और खेतों को उजाड़ने की साजिश को किसी कीमत पर मुझे स्वीकार नही। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की डी एम नवादा द्वारा धज्जी उड़ाया जा रहा है। गरीबों का मकान और खेत उजाड़े जा रहे है। कानून तोड़कर बिना सोशल ऑडिट और 70 प्रतिशत किसानों की बिना सहमति एवं जमीन का मुआबजा दिए,जबरन जमीन छीना जा रहा है। काली सूचि के ठेकेदार के खिदमत में गैर कानूनी ढंग से समाहरणालय में बैठकर फर्जी सोशल ऑडिट कर खेतों में लहलहाते धान के फसलों को इस बरसात के मौसम में बुलडोजर से रौंदा गया है। आज सर्वसम्मति से मोतनाजे एवं मधुबन के लोगों ने फैसला लिया कि हम जान देंगे,परन्तु अपनी जमीन नहीं देंगे। करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करेंगे। टिकैत ने कहा अभी भी यह देश लोगों का लोकतंत्र है। इसलिए लोग ही महापंचायत में इस इलाके के सभी भाईयों एवं बहनों का सर्वसम्मत फैसला है,ना हमें खनन चाहिए ना पर्यटन चाहिए। हम सब मिलकर एक जूट है और अपने अंतिम सांस तक मिलकर लड़ेंगे। आपका पानी,जवानी और किसानी सब बाहर जा रहा है। हमारी यह महापंचायत फैसला लेती है कि वैसा विकास हमें नहीं चाहिए,जो किसानी और गाँव के लिए विनाशकारी हो ।हमारी जवानी,पानी और किसानी को विकसित करने वाली विकास हमें चाहिए ।यह महापंचायत राज्य और देश की हुकूमत को बताना चाहती है कि विनाशकारी विकास हमें नहीं चाहिए। जब तक गांव प्रधान और कृषि प्रधान भारत में गांव और कृषि के विकास की नीति नहीं बनेगी,तब तक देश का विकास नहीं होगा। सबसे अच्छी मिट्टी और सबसे अच्छा पानी बिहार की है। फिर भी सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण यहाँ बिहारी गरीब हैं। पानी का बाजारी कारण और व्यापरीकरण नहीं, उसका समुदायिकरण चाहिए। किसान नेता दिनेश सिंह ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार के हजारों गांव की जल,जंगल और जमीन पर मोदी के प्यारे मित्र कार्पोरेटो की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है।

एक नजर

आर्कटिक ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं पीवी सिंधु, तन्वी शर्मा बाहर

वांता (फिनलैंड),एजेंसी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने गुरुवार को जापान की रिको गुंजी को हराकर आर्कटिक ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि तन्वी शर्मा को शीर्ष वरीयता प्राप्त थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने गुंजी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 21-9, 21-12 से आसान जीत दर्ज की। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त इंतानोन से होगा। इस मुकाबले की विजेता खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। इंतानोन ने दूसरे दौर के मुकाबले में तन्वी शर्मा को 21-18, 21-7 से हराया। तन्वी ने पहले गेम में चुनौती पेश की, लेकिन दूसरे गेम में इंतानोन ने दबदबा बनाते हुए सीधे गेम में मुकाबला अपने नाम कर लिया। सिंधु और इंतानोन के बीच आमने-सामने के रिकॉर्ड में थाई खिलाड़ी का पलड़ा भारी है। दोनों के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं, जिनमें इंतानोन ने 10 और सिंधु ने चार मुकाबले जीते हैं। दोनों खिलाड़ियों की पिछली भिड़ंत 2022 में इंडोनेशिया मास्टर्स में हुई थी, जहां इंतानोन ने सिंधु को 21-12, 21-10 से हराया था।

बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी के लिए हिमाचल की सीनियर मेन टीम घोषित, पुखराज मान को मिली कमान

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी एलीट टूर्नामेंट के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कमान पुखराज मान को सौंपी गई है। टीम में अन्य खिलाड़ियों में शुभम अरोड़ा, आकाश वशिष्ठ, अर्पित गुलेरिया, इनेश महाजन, हर्षित चंदन, आर्यमन धालीवाल, नेहल वढेरा, जितेन्द्र, मुकुल नेगी, वैभव कालटा, दिवेश, अमनप्रीत सिंह, रितिक कालिया तथा नितिन शर्मा शामिल है। टीम में विनीत सक्सेना मुख्य कोच, गगनदीप सिंह बॉलिंग कोच, शकुन सैनी फील्डिंग कोच, सौरव ठाकुर फिजियो, जरनैल सिंह अनुसूचित जाति, राज किरीट कपाड़िया वीडियो विश्लेषक, ब्रजेश शर्मा मालिश करनेवाला, भूपेश्वर पार्श्व भुजा, पुनित सैनी पार्श्व भुजा जबकि राजेश पुरी को प्रबंधक नियुक्त किया गया है।

हिमाचल के मैचों का शेड्यूल

रणजी प्रतियोगिता में हिमाचल एलीट ग्रुप में सात मैच खेलेगा। इन सात मैचों में तीन मैच घरेलू मैदान धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक हिमाचल 11 से 14 अक्टूबर तक हरियाणा के साथ अपना पहला मैच लाहली में खेलेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश बनाम मुंबई 18-21 अक्टूबर को बिलासपुर में, हिमाचल बनाम चंडीगढ़ 26-29 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश बनाम राजस्थान 2-5 नवंबर धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश बनाम तमिलनाडु 17-20 जनवरी तक, हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तराखंड 24-27 जनवरी 2027 को धर्मशाला में तथा हिमाचल प्रदेश बनाम रेलवे चार-दिवसीय 1-4 फरवरी 2027 तक धर्मशाला में खेलेगा।

बेंगलुरु एफसी की नजर जीत के साथ आईएसएल आगाज पर, उद्घाटन मैच की मेजबानी करेगा

बेंगलुरु। बेंगलुरु एफसी शनिवार को श्री कांतीरवा स्टेडियम में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ मुकाबले से 2026-27 एमजी इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) अभियान की शुरुआत करेगा। लीग का पहला मुकाबला होने के साथ ही बेंगलुरु पहली बार आईएसएल के उद्घाटन मैच की मेजबानी करेगा। पिछले सत्र में 13 मैचों में छह जीत, पांच ड्रॉ और दो हार के साथ 23 अंक जुटाकर चौथे स्थान पर रही बेंगलुरु की टीम जीत के साथ नए सत्र का आगाज करना चाहेगी। उसने पिछले अभियान का अंत चेन्नईयिन एफसी को 2-1 से हराकर किया था। टीम में इस बार स्पेन के बोरजा मार्टिनेज, पुर्तगाल के सैंड्रो एम्बालो, अर्जेंटीना के मैनुएल डी इरियोन्डो, नीदरलैंड्स के मेन्नो कोच और मोंटेनेग्रो के मिहाइलो पेरोविच जैसे विदेशी खिलाड़ी जुड़े हैं। वहीं सोहम वर्षनेया, विनित वेंकटेश और हर्ष पालांडे के करार बढ़ाए गए हैं। कप्तान सुनील छेत्री भी टीम के साथ बने हुए हैं। मुख्य कोच पेप मुनोज के लिए यह क्लब के साथ पहला पूर्ण सत्र है। उन्होंने कहा कि टीम लंबे प्री-सीजन के बाद मुकाबले के लिए तैयार है और घरेलू मैदान पर समर्थकों के सामने सकारात्मक शुरुआत करना चाहती है। मिडफील्डर सुरेश वांगजम ने भी मजबूत शुरुआत का लक्ष्य जताया।

देशभर के 500 खिलाड़ी जोधपुर में खेलेंगे साइकिल पोलो

जोधपुर। जोधपुर में 15 से 18 नवम्बर तक राष्ट्रीय साइकिल पोलो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में देश के 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से करीब 500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्रबंधक एवं खेल अधिकारी भाग लेंगे। शिवराज सिंह के निर्देशन में आयोजित होने वाला यह आयोजन देश के सबसे बड़े साइकिल पोलो खेल आयोजनों में शामिल होगा। प्रतियोगिता में विश्व विजेता भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर शिवराज सिंह के निर्देशन में विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें राज मारवाड़ खेल महोत्सव के पदाधिकारियों ने भाग लिया और आयोजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। राज मारवाड़ खेल महोत्सव के मानद उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी खिलाडियों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों एवं खेल अधिकारियों के ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था राज मारवाड़ खेल महोत्सव की ओर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में करीब दोगुने खिलाड़ी एवं खेल अधिकारी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। यह भारत का सबसे बड़ा वार्षिक साइकिल पोलो आयोजन है और इस वर्ष इसकी मेजबानी जोधपुर को मिली है। मुख्य सचिव मनोज मालानी ने बताया कि करीब 15 वर्षों बाद जोधपुर के पोलो खिलाडियों और खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के साइकिल पोलो मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के राष्ट्रीय विजेताओं को पूर्व नरेश गजसिंह की ओर से रनिंग ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं शिवराज सिंह की ओर से सभी वर्गों में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाडियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। मालानी ने बताया कि राजस्थान साइकिल पोलो टीम भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी।

नाना पाटेकर के निधन पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कप्तान रहाणे ने जताया शोक

नई दिल्ली,एजेंसी। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर भारतीय क्रिकेट जगत से भी श्रद्धांजलियों का सिलसिला जारी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे और पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अभिनेता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके अभिनय तथा सामाजिक कार्यों को याद किया।

राजीव शुक्ला ने नाना पाटेकर को 'बेहद संवेदनशील इंसान' बताते हुए कहा कि उनके शानदार अभिनय, बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'दिग्गज अभिनेता और बेहद संवेदनशील इंसान श्री नाना पाटेकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उनके शानदार अभिनय कौशल, बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। फिल्मों की दुनिया से परे, समाज सेवा के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण और लोगों के जीवन को बदलने के उनके प्रयासों ने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करे। उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नाना पाटेकर को 'बेहद शानदार अभिनेता' बताते हुए कहा कि उनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और मनोरंजन किया। रहाणे ने एक्स पर लिखा, 'नाना पाटेकर जी वास्तव में एक बेहद शानदार अभिनेता थे, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और मनोरंजन किया। उनके निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने अभिनेता को भारतीय सिनेमा की 'बेहद खास प्रतिभा' बताया और कहा कि उनका काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। धवन ने एक्स पर लिखा, 'आज भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास प्रतिभा खो दी है। नाना पाटेकर साहब, आपका काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ? शांति। नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 5:20 बजे उनके आवास पर हृदयाघात के बाद निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। हिंदी और मराठी सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में शामिल नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म 'गमन' से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'परिंदा', 'प्रहार', 'अंगार', 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'खामोशी' और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई। अपने करियर के अंतिम दौर में भी नाना पाटेकर फिल्मों में सक्रिय रहे। वह अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख अभिनीत 'हाउसफुल 5' का हिस्सा थे। उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ'रोमियो' में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके अलावा वह अनिल कपूर और राधिका मदान अभिनीत 'सूबेदार' में भी विशेष भूमिका में नजर आए थे।

वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में हरमनजोत सिंह और लिली दास भारतीय एलीट वर्ग की करेंगे अगुवाई

नई दिल्ली। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के आयोजक प्रोकेम इंटरनेशनल ने गुरुवार को 21वें संस्करण के लिए भारतीय एलीट धावकों की घोषणा की। विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रोड रेस का आयोजन 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा, जिसमें 22 पुरुष और 20 महिला भारतीय एलीट धावक हिस्सा लेंगे।

पुरुष वर्ग में हरमनजोत सिंह और किरण माट्रे भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। हरमनजोत 2026 टीसीएस वर्ल्ड 10के बेंगलुरु के भारतीय एलीट चैंपियन और 2026 एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं। वह 18 अक्टूबर को पहली बार वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लेंगे। हरमनजोत का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 1 घंटा 1 मिनट 46 सेकंड है, जो भारतीय एलीट क्षेत्र में सबसे तेज समय है। उन्होंने अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन में यह समय दर्ज किया था। हरमनजोत ने कहा, 'इस साल बेंगलुरु में जीत और एशियाई क्रॉस कंट्री में रजत पदक ने दिल्ली जाने से पहले मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ाया है। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन देश की सबसे कठिन दौड़ों में से एक है, जहां ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। मैं हाफ मैराथन में सर्वश्रेष्ठ एलीट धावकों के खिलाफ खुद को परखने के लिए उत्सुक हूं। रेस के दिन मैं अपना सबकुछ झोंक दूंगा। पिछले साल वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय एलीट पुरुष वर्ग में दूसरे स्थान पर रहे किरण माट्रे भी इस बार मजबूत चुनौती पेश करेंगे। उन्होंने इसी दौड़ में 1 घंटा 4 मिनट 57 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय बनाया था। वह 2024 में टीसीएस वर्ल्ड 10के बेंगलुरु की भारतीय एलीट दौड़ के विजेता भी रहे हैं, जहां उन्होंने 29 मिनट 32 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया था। पुरुष वर्ग में उन्हें 2026 टाटा मुंबई मैराथन के भारतीय एलीट विजेता डॉ. कार्तिक करकेरा से भी कड़ी चुनौती मिलेगी। करकेरा पिछले साल वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में तीसरे स्थान पर रहे थे। उत्तर प्रदेश के ट्रैक धावक प्रिंस कुमार भी लंबे अंतराल के बाद हाफ मैराथन में वापसी करेंगे। उन्होंने 2025 ओपन राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर के खिताब जीते थे। इसके अलावा वह 2025 दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 मीटर के स्वर्ण पदक विजेता रहे।

श्रीकांत और प्रणय आर्कटिक ओपन के पहले दौर में बाहर

वांता (फिनलैंड)। विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय को बुधवार को यहां आर्कटिक ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक्स डॉट कॉम के अनुसार, दुनिया के 31वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत को कनाडा के 34वें नंबर के ब्रायन यांग ने 15-21, 21-15, 21-13 से हराया। श्रीकांत ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए पहला गेम अपने नाम किया लेकिन यांग ने अगले दोनों गेम जीतकर भारतीय खिलाड़ी की चुनौती समाप्त कर दी। दुनिया के 38वें नंबर के प्रणय को चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन के खिलाफ 21-10, 21-9 से शिकस्त झेलनी पड़ी। प्रणय पूरे मुकाबले में संघर्ष करते नजर आए और सीधे गेम में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

हालांकि, पुरुष युगल में भारत को कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने बड़ी जीत दिलाई। गैरवरीय भारतीय जोड़ी ने पांचवीं वरीयता प्राप्त चीन के हे जी तिंग और रेन शियांग यू को 61 मिनट चले मुकाबले में 10-21, 21-18, 22-20 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए अगले दोनों गेम जीत लिए। पुरुष एकल में थारुन मन्नेपल्ली ने भारत की उम्मीदें कायम रखीं। क्वालीफायर के जरिए मुख्य दौर में पहुंचे थारुन ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 21-16, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से होगा। क्वालीफायर के जरिए मुख्य दौर में पहुंचे रौनक चौहान को चीन के वेंग होंग यांग के खिलाफ कड़े मुकाबले में 22-20, 20-22, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। रौनक ने पहला गेम गंवाने के बाद दूसरे गेम में वापसी करते हुए मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया लेकिन वेंग ने तीसरा गेम जीतकर भारतीय खिलाड़ी का सफर समाप्त कर दिया। महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और तान्वी शर्मा गुरुवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का सामना जापान की रिको गुंजी से होगा, जबकि तान्वी शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी।

हरमनप्रीत की कप्तानी पर झूलन ने कहा- नेतृत्व सिर्फ कप्तानी का बैज पहनना नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने सभी प्रारूपों में भारतीय महिला टीम की कप्तानी छोड़ने वाली हरमनप्रीत कौर की सराहना की है। उन्होंने हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट के महत्वपूर्ण पड़ावों को याद करते हुए कहा कि कप्तानी छोड़ना उनके करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत है। हरमनप्रीत ने हाल ही में भारत को पहली बार सीनियर महिला वनडे विश्व कप खिताब दिलाने के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। उनकी जगह स्मृति मंधाना को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। हालांकि, हरमनप्रीत जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा बनी हुई हैं।

झूलन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'नेतृत्व सिर्फ कप्तानी का बैज पहनना नहीं है, बल्कि टीम की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाना, उतार-चढ़ाव के बीच मजबूती से खड़े रहना और खेल को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़ना है।' उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत ने साहस, मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ भारतीय महिला क्रिकेट का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम की जिम्मेदारी गर्व के साथ संभाली। झूलन ने कहा कि कप्तानी से हटने के बाद हरमनप्रीत अब खेल को और अधिक स्वतंत्रता के साथ खेल सकेंगी। उन्होंने हरमनप्रीत को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'खुले मन, जुनून और उसी जज्बे के साथ खेलती रहें, जिसने आपको हमेशा चैंपियन बनाया है। हरमनप्रीत 2018 से भारत की पूर्णकालिक टी20 कप्तान थीं और 2022 में मिताली राज से वनडे टीम की कमान संभाली थी। उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला सीनियर महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता। टीम ने घरेलू मैदान पर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी कप्तानी में भारत ने 2012, 2016, 2022 और 2026 में चार एशिया कप खिताब तथा 2022 और 2026 में लगातार दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 1999 के बाद पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट जीत और 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत भी उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रही।

कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पारस और ध्वज ने दिलाई भारत को मजबूत शुरुआत

अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 के शुरुआती दिन भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को खेले गए मुकाबलों में पारस गुप्ता और ध्वज हरिया ने अपने-अपने वर्ग में प्रभावी जीत दर्ज की।

पुरुषों के हेयबॉल में पारस गुप्ता ने समोआ के रिवेलेशन टैगालोआ को 8-3 से हराया, जबकि उजैर खान ने हुसैन अब्दुल्ला को 9-4 से शिकस्त दी। अगले दौर में पारस का सामना क्रेग ब्राउन और उजैर का मुकाबला टैन झोंग वेई से होगा। नूकर में ध्वज हरिया ने आइल ऑफ मैन के क्रिस डैगनल को 3-0 से हराया। वहीं लक्ष्मण सिंह रावत ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड राइट को कड़े मुकाबले में 3-2 से मात दी। केतन चावला का मुकाबला आइल ऑफ मैन के माइकल कर्पे से हुआ।

महिला स्नूकर में स्नेन्थरा बाबू ने नताशा केंट को 3-1 और श्रुति लक्ष्मीनारायणन ने ऑस्ट्रेलिया की जेसिका वुड्स को 3-1 से हराया। महिला बिलियर्ड्स में अनुपमा रामचंद्रन ने चिम्बा चिम्फ्वेम्बे को मात देकर अभियान की शुरुआत जीत से की। 10-बॉल में लालरिना रेंथलेई ने केली यांबी को 9-3 से हराया, जबकि दिव्या शर्मा ने डार्सी मैकगिनले के खिलाफ जीत दर्ज की। पुरुष बिलियर्ड्स में सिद्धार्थ पारिख ने क्लाइव मार्श को हराया। महिला ब्लैकबॉल में जियाना रेगो ने थापेलो मोथाते को 5-2 से मात दी। हालांकि, कुछ स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों को हार का भी सामना करना पड़ा। महिला हेयबॉल में जिया सहगल एग्नेस किमुरा से 2-4 और विद्या पिल्लई दक्षिण अफ्रीका की मरीना जैकब्स से 2-7 से हार गईं। पुरुष ब्लैकबॉल में चेतन छाबड़ा और आरव सांचेती को क्रमशः रवांडा के फ्रेडरिक नगाबोयिसोंगा और ली शेफर्ड ने 7-4 तथा 7-2 से हराया। महिला 10-बॉल में सानवी शाह को सिंगापुर की एनरान यू से 1-7 से हार मिली।

विधायक स्वर्गीय नीलम करवरिया कप में 12 विधानसभा क्षेत्रों की टीमें लेंगी हिस्सा

प्रयागराज। पूर्व विधायक स्वर्गीय नीलम करवरिया की स्मृति में नीलम करवरिया कप-2026 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 10 अक्टूबर से किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार सुबह आठ बजे केपी ग्राउंड स्थित मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान में होगा। प्रतियोगिता में प्रयागराज जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की 12 विधानसभा क्षेत्रों की टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रयागराज के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी टीमों का चयन संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित तिथियों पर किया गया है। विधानसभा क्षेत्र की टीम में उसी विधानसभा क्षेत्र का मूल निवासी खिलाड़ी होना अनिवार्य रखा गया है। प्रत्येक टीम के कोच और मैनेजर को भी अधिकृत किया गया है। टीमों में आवश्यकता के अनुसार दो बाहरी खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

प्रतियोगिता का संचालन प्रयागराज क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध पंजीकृत अंपायर, स्कोरर, रेफरी और कमेंटेटर करेंगे। मैचों को निर्विवाद रूप से संपन्न कराने के लिए तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है। सभी मुकाबलों का यू-ट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रतियोगिता में गेंद आयोजन समिति की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजन सचिव सक्षम करवरिया ने बताया कि प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी के साथ दो हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक को ट्रॉफी के साथ 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ट्रॉफी और 20 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को नीलम करवरिया कप के साथ एक लाख रुपये तथा उपविजेता टीम को कप के साथ 60 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा विजेता और उपविजेता टीम के सभी खिलाड़ियों, कोच और मैनेजर को क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। आयोजन सचिव सक्षम करवरिया ने बताया कि 'नीलम करवरिया कप का उद्देश्य प्रयागराज के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की प्रतिभाओं को बेहतर मंच देना है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को बिना किसी शुल्क के अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि आयोजन पारदर्शी और बेहतर खेल भावना के साथ संपन्न हो तथा उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

एक नजर

अमेरिका ने इंफोसिस, टाटा, विप्रो समेत प्रमुख आईटी कंपनियों को ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से हटाया

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका ने विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर चिंता जताते हुए इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी समेत कई बड़ी आईटी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (पीईआरएम) कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट और एडोब को भी इस कार्यक्रम से बाहर किया गया है। अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों से जुड़ी नई स्थायी श्रम प्रमाणन अर्जियां स्वीकार नहीं की जाएंगी और लंबित अर्जियों पर भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। पीईआरएम अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का अहम चरण है। इसके तहत कंपनियों को यह प्रमाणित करना होता है कि संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इस कार्रवाई से कंपनियों के मौजूदा एच-1बी वीजा अपने आप रद्द नहीं होते। सॉन्डरलिंग ने दावा किया कि सूची में शामिल कंपनियों ने 2009 से अब तक करीब 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए आवेदन किए हैं। उनके अनुसार, इन्हें 2.30 लाख से अधिक एच-1बी वीजा मंजूर हुए और एक लाख से अधिक स्थायी श्रम प्रमाणन मिले हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस कदम को अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा और विदेशी श्रमिकों से जुड़े वीजा कार्यक्रमों में कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई से जोड़ा है। उपराष्ट्रपति वेंस ने विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट पर कार्यक्रम के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

इबोला से मुकाबले में केन्या के साथ खड़ा है भारत

नैरोबी,एजेंसी। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के प्रयासों में केन्या के साथ एकजुटता जताते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और आपात प्रतिक्रिया में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के लंबे सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय उच्चायोग ने यह बयान केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) से आए एक यात्री में इबोला संक्रमण की पुष्टि किए जाने के बाद दिया। संक्रमित यात्री की 06 अक्टूबर को मौत हो गई थी। केन्याई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह एक आयातित मामला है और इससे देश में व्यापक संक्रमण का संकेत नहीं मिलता। भारत ने इबोला से निपटने के लिए केन्या को 6,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट भी उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुआले ने राजनयिकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विकास साझेदारों के साथ बैठक में देश की तैयारियों की जानकारी दी। केन्या में मई 2026 से राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्रणाली सक्रिय है और राष्ट्रीय व काउंटी स्तर की आपात प्रतिक्रिया इकाइयों को सतर्क रखा गया है। स्वास्थ्य केंद्रों और समुदायों में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा संभावित मामलों की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात हैं। मंत्रालय के अनुसार, 4,971 स्वास्थ्यकर्मियों को इबोला से बचाव और निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है। देश के 15 प्रवेश बिंदुओं पर जांच जारी है और अब तक 6.52 लाख से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

दक्षिणी लेबनान में किसी भी तरह का सुरक्षा शून्य नहीं पैदा होना चाहिए : काजा कलास

बेरूत। यूरोपीय संघ (ईयू) की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि यूरोपीय संघ लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के जनादेश को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान में किसी भी तरह का सुरक्षा शून्य पैदा नहीं होना चाहिए। लेबनान के दौरे के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद कलास ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने यूएनआईएफआईएल का मौजूदा जनादेश समाप्त होने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, 'अगर इस जनादेश को बढ़ाया जाता है, तो इसका स्वागत किया जाएगा। यही सदस्य देशों की स्थिति है। यूएनआईएफआईएल में करीब 50 देशों के लगभग 7,500 जवान तैनात हैं। यह मिशन 1978 से दक्षिणी लेबनान में मौजूद है। हालांकि, इसकी मौजूदगी के बावजूद क्षेत्र में कई बार संघर्ष भड़क चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले वर्ष अमेरिका के दबाव में यूएनआईएफआईएल का जनादेश 31 दिसंबर 2026 को समाप्त करने का फैसला किया था। कलास ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता वाले इजरायल-लेबनान समझौते के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए किसी पक्ष या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है कि दोनों पक्ष अपने वादों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूएनआईएफआईएल का मिशन समाप्त हो जाता है और उसकी जगह निगरानी के लिए कोई नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तैयार नहीं होती, तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है।

बांग्लादेश में शारदीय नवरात्रि पर सुरक्षा का जिम्मा अंसार और वीडीपी को

ढाका (बांग्लादेश)। देश में शारदीय नवरात्रि और इस अवसर पर सजने वाले दुर्गा पंडालों की सुरक्षा बांग्लादेश अंसार एंड विलेज डिफेंस पार्टी (वीडीपी) को सौंपा गया है। बांग्लादेश अंसार एंड विलेज डिफेंस पार्टी गृह मंत्रालय के अधीन सहायक अर्धसैनिक बल है। इस बल ने शारदीय दुर्गा पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पूरे देश में सुरक्षा के अग्रिम उपाय शुरू कर दिए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार देररात जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बल के सदस्यों ने देशभर में मूर्ति बनाने वाली जगह, पूजा पंडालों और मंदिरों का दौरा शुरू कर दिया है। आयोजन समितियों के नेताओं, मंदिर अधिकारियों और मूर्ति बनाने वालों के साथ बातचीत की जा रही है। यह उपाय बांग्लादेश अंसार एंड विलेज डिफेंस पार्टी के महानिदेशक मेजर जनरल अब्दुल मोतालेब सज्जाद महमूद के निर्देश पर जिला और उपजिला स्तर पर किए जा रहे हैं। बताया गया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय पर भी जोर दिया जा रहा है। महानिदेशक ने दुर्गा पूजा पंडालों में समग्र सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने तथा आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई करने में सहयोग करने के लिए भी कहा है। दुर्गा पंडालों में बल के सदस्यों को भी तैनात करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

नेपाल में बाढ़ प्रभावितों के लिए ऑस्ट्रेलिया देगा अतिरिक्त 15 मिलियन डॉलर की सहायता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग के बीच नेपाल-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। गुरुवार को मेलबर्न में हुई बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने तथा आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। विदेशमंत्री खनाल के सचिवालय के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से कायम घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। लोकतांत्रिक मूल्यों, पारस्परिक सम्मान और मजबूत जनस्तरीय संबंधों पर आधारित सहयोग को आगे और विस्तार देने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों और समुदायों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद राहत, शुरुआती पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों में ऑस्ट्रेलिया नेपाल के साथ खड़ा है।

वोंग ने बाढ़ और आपदा प्रभावित नेपाल के लिए अतिरिक्त 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 161 करोड़ नेपाली रुपये) की सहायता देने की घोषणा की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 11 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई थी। नई सहायता राशि राहत और शुरुआती पुनर्वास कार्यों पर खर्च की जाएगी। विदेश मंत्री खनाल ने संकट के समय ऑस्ट्रेलियाई सरकार और वहां के लोगों की ओर से मिली त्वरित और उदार मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय मिली यह एकजुटता नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। बैठक में नेपाल और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रहे साझा जोखिमों पर भी चर्चा हुई। खनाल ने ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय नेतृत्वकारी भूमिका का उपयोग करते हुए, विशेष रूप से आगामी सीओपी-31 के संदर्भ में, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के असमान और गंभीर प्रभावों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया। उन्होंने जलवायु अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा तैयारी और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण में नेपाल-ऑस्ट्रेलिया सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने शैक्षिक सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा की। नेपाल में ऑस्ट्रेलिया से मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के संभावित सैटेलाइट कैंपस नेपाल में स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। खनाल ने ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज और अर्थव्यवस्था में नेपाली विद्यार्थियों तथा नेपाली डायस्पोरा के योगदान का उल्लेख करते हुए हाल में हुए छात्र वीजा संबंधी नीतिगत बदलावों के बीच वास्तविक और योग्य नेपाली विद्यार्थियों के लिए अनुकूल एवं न्यायसंगत व्यवस्था करने का आग्रह किया। बैठक में नेपाल-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने को भी प्राथमिकता दी गई। व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तकनीक हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, पर्यटन और श्रम गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने के विषय पर भी बातचीत हुई।

भारी बर्फबारी से हिल्सा-सिमकोट सड़क बंद, चीन के पुरंग में फंसे करीब 300 नेपाली

काठमांडू। नेपाल-चीन सीमा पर हिल्सा-सिमकोट सड़क मार्ग पर भारी बर्फ गिरने से आवागमन बाधित होने के बाद हुम्ला से चीन गए करीब 300 नेपाली नागरिक तिब्बत के पुरंग में फंस गए हैं। सड़क बंद होने के कारण वे नेपाल वापस नहीं लौट पा रहे हैं और चीन में ही रहने को मजबूर हैं। पुरंग में मौजूद साम चेन द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी के अनुसार, हुम्ला के विभिन्न स्थानीय निकायों के करीब 300 नेपाली नागरिक इस समय पुरंग में रुके हुए हैं। इनमें अकेले नाम्खा गांवपालिका के 150 से अधिक नागरिक शामिल हैं। चेन के अनुसार, बर्फबारी के कारण हिल्सा से सिमकोट आने वाला सड़क मार्ग बंद है। इसलिए वे घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हुम्ला के विभिन्न स्थानीय निकायों के नागरिकों के अलावा भारत से आए कुछ लोग भी पुरंग में फंसे हुए हैं। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के डारी प्रीफेक्चर में स्थित पुरंग काउंटी, हुम्ला के हिल्सा नाके से जुड़ा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। हुम्ला से व्यापार, रोजगार और अन्य कामों के लिए पुरंग गए नेपाली नागरिक सड़क बंद होने के बाद वहीं रुक गए हैं। हिल्सा से सिमकोट लौटने वाले मार्ग पर भारी बर्फ जमने के कारण वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। पैदल आवागमन भी जोखिमपूर्ण हो गया है। ऐसे में नेपाली नागरिक पुरंग में ही रहने को मजबूर हैं। पुरंग में फंसे नागरिकों का कहना है कि जब तक बर्फ हटाकर सड़क को चालू नहीं किया जाता, तब तक नेपाल लौटना संभव नहीं है। लंबे समय से सड़क बंद रहने के कारण उनके रहने, खाने-पीने और अन्य दैनिक जरूरतों पर भी असर पड़ने लगा है। हुम्ला के प्रमुख जिला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईं ने बताया कि हिल्सा-सिमकोट सड़क पर बर्फ जमा होने के कारण चीन की ओर गए व्यापारी और स्थानीय लोग वहीं रुके हुए हैं।

उनके अनुसार, पुरंग क्षेत्र में जमा बर्फ हटाए जाने के बाद ही हिल्सा के रास्ते हुम्ला लौटने की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा, 'हिल्सा से सिमकोट आने वाली सड़क पर बर्फ होने के कारण व्यापारी और स्थानीय लोग ताक्लाकोट की ओर रुके हुए हैं। रास्ता नहीं खुलने तक फिलहाल समस्या बनी हुई है। सड़क बंद होने से हुम्ला के उत्तरी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां और स्थानीय लोगों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। खासकर चीन के पुरंग पहुंचे नेपाली नागरिक सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बर्फबारी के कारण यदि लंबे समय तक सड़क नहीं खुली तो पुरंग में फंसे नेपाली नागरिकों की परेशानी और बढ़ सकती है।

नेपाल में अमेरिकी परियोजना एमसीसी कॉम्पैक्ट की अवधि एक साल बढ़ेगी

काठमांडू। नेपाल वित्त मंत्रालय के अनुसार, नेपाल और अमेरिका के बीच मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कॉम्पैक्ट के कार्यान्वयन की अवधि को अधिकतम एक वर्ष बढ़ाने को लेकर सहमति करीब पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद विदेशी सहायता की समीक्षा के कारण एमसीसी से वित्तपोषित परियोजनाओं का काम कई महीनों तक प्रभावित रहा। इसके अलावा, त्रिशूली नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है। इन्हीं कारणों से अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

एमसीसी कॉम्पैक्ट के तहत परियोजनाओं को आम तौर पर समझौते के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर पूरा करना होता है। नेपाल का एमसीसी कॉम्पैक्ट 30 अगस्त 2023 को लागू हुआ था। इसके अनुसार परियोजनाएं अगस्त 2028 तक पूरी होनी है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित विस्तार 'नो-कॉस्ट एक्सटेंशन' होगा। यानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए परियोजना की कुल लागत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस मुद्दे पर वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान भी चर्चा हुई। उन्होंने एमसीसी के कार्यवाहक उपाध्यक्ष जेसन स्मॉल से मुलाकात की थी। मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, दोनों पक्ष इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए कि जरूरत पड़ने पर अवधि बढ़ाकर भी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना चाहिए। मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल पहले ही वित्त मंत्रालय के समक्ष अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर चुका है। अब वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जाना होगा। इसके बाद नेपाल सरकार औपचारिक रूप से अपना निर्णय एमसीसी को भेजेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, एमसीसी बोर्ड दिसंबर में होने वाली अपनी बैठक में नेपाल के अनुरोध पर विचार कर सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अभी तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पेश नहीं किया है। अमेरिका के वित्त वर्ष 2026 के विनियोग कानून में भी नेपाल के एमसीसी कॉम्पैक्ट की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह धनराशि की उपलब्धता और संबंधित अमेरिकी कांग्रेस समितियों को सूचना दिए जाने की शर्त पर निर्भर करेगा। नेपाल और अमेरिका ने 14 सितंबर 2017 को एमसीसी कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

जलवायु आपदा पर नेपाल का आपातकालीन प्रस्ताव आईपीयू महासभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित

काठमांडू,एजेंसी। तंजानिया के अरुशा में जारी अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 153वीं महासभा में नेपाल द्वारा प्रस्तुत जलवायु जनित आपदाओं से संबंधित आपातकालीन प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित हो गया है। नेपाली संसद के स्पीकर डोल प्रसाद (डीपी) अर्याल द्वारा प्रस्तुत 'हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जलवायु संबंधी आपदाओं से निपटने और लचीलापन मजबूत करने के लिए तत्काल संसदीय कदम' शीर्षक वाले आपातकालीन एजेंडे को महासभा में दो-तिहाई बहुमत मिला।

इस अवसर पर स्पीकर अर्याल ने हिमालय को मानवता की साझा विरासत और एशिया का 'वाटर टावर' बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय, ग्लेशियरों और हिमतालों पर बढ़ता खतरा पूरी मानव सभ्यता के लिए चुनौती बन रहा है। नेपाल द्वारा हाल में झेली गई जलवायुजनित आपदाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु न्याय और संसदीय जवाबदेही के लिए दुनिया की संसदों के बीच साझा जिम्मेदारी और सहयोग आवश्यक है। अर्याल ने कहा कि महासभा द्वारा नेपाल के प्रस्ताव को पारित किया जाना केवल नेपाल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आईपीयू के सभी सदस्य देशों और सांसदों की भी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने जलवायुजनित आपदाओं से निपटने के लिए संसदीय जलवायु कूटनीति को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। प्रस्ताव में सदस्य देशों के बीच जलवायु और मौसम संबंधी सीमापार पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित देशों की कार्यपालिका को संसदीय स्तर से जवाबदेह बनाने की आवश्यकता भी प्रस्ताव में उठाई गई है। स्पीकर अर्याल ने विश्व समुदाय से दोषारोपण के बजाय जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा, न्याय और सुरक्षित भविष्य के लिए साझा समाधान विकसित करने का आह्वान किया। आपातकालीन प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के उद्देश्य से सभामुख अर्याल ने महासभा के सदस्यों से समर्थन मांगा था।

प्रस्ताव पर मतदान
- पक्ष में: 901 वोट
- विपक्ष में: 78 वोट
- तटस्थ: 140 वोट

आईपीयू महासभा के नियम 11(ख) के अनुसार, यदि एक से अधिक आपातकालीन प्रस्ताव आवश्यक बहुमत हासिल करते हैं, तो सबसे अधिक सकारात्मक वोट पाने वाले प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया जाता है। इसी व्यवस्था के तहत सबसे अधिक सकारात्मक मत प्राप्त करने वाले नेपाल के प्रस्ताव को आपातकालीन विषय के रूप में चुना गया। अब नेपाल के प्रस्ताव पर आईपीयू की 153वीं महासभा के आपातकालीन एजेंडे के तहत चर्चा होगी। चर्चा में जलवायुजनित आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों, हिमालय और ग्लेशियरों के संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग तथा जोखिम वाले क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने के लिए आवश्यक संसदीय पहलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कनाडा की लेखिका ऐन कार्सन को मिलेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम,एजेंसी। कनाडा की लेखिका ऐन कार्सन को वर्ष 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें प्राचीन ग्रीक-रोमन साहित्य को नए तरीके से पेश करने और लेखन के नए प्रयोग के लिए यह सम्मान मिलेगा। नोबेल समिति के सदस्यों ने स्टॉकहोम में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्सन के नाम की घोषणा की। नोबेल समिति ने कहा कि 76 वर्षीय कार्सन अपनी उन रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर कविता, कथा-साहित्य और अकादमिक अध्ययन के बीच की सीमाओं को पार करती हैं। यह पुरस्कार उनकी साहसिक और रचनात्मक साहित्यिक कृतियों के लिए दिया गया है, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा के साथ रोचक संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूपों का स्थापित किया है।

नोबेल पुरस्कार किसी लेखक के पूरे जीवन के साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। इसे विश्व साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। नोबेल समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन के मुताबिक कार्सन का जन्म 21 जून, 1950 को टोरंटो में हुआ था। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वे 1979 से अमेरिका और कनाडा के कई विश्वविद्यालयों में क्लासिक्स, तुलनात्मक साहित्य और क्रिएटिव राइटिंग विषय पढ़ा रही हैं। ओल्सन के मुताबिक कार्सन का साहित्य प्राचीन यूनानी परंपरा और आधुनिक जीवन के अनुभवों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। कविता, अनुवाद, निबंध, कथा और दृश्य कलाओं के बीच नए संबंध स्थापित करने की उनकी क्षमता ने 1990 के दशक से अंतरराष्ट्रीय साहित्य और कला जगत पर गहरा प्रभाव डाला है। कार्सन ने 1981 में क्लासिक्स विषय में 'ओडी एट अमो एर्गो सम' नाम से डॉक्टरेट थीसिस प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने कविता लिखने के साथ प्राचीन ग्रीक साहित्य का अनुवाद और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम किया। उनकी रचनाओं में शब्दों की उत्पत्ति और उनके नए अर्थ पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने यूनानी कवयित्री सैफो की कविताओं और नाटककार सोफोक्लीज की इलेक्ट्रा और एंटीगनी का भी अनुवाद किया है। नोबेल समिति के मुताबिक शुक्रवार को वर्ष 2026 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इससे पहले भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। पिछले 10 साल में साहित्य का नोबेल 10 लेखकों को मिला, जिनमें 5 महिलाएं थीं। इनमें 6 ने अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में लिखा, जबकि 6 विजेता यूरोप से रहे। वर्ष 2024 में दक्षिण कोरिया की हान कांग एशिया से पुरस्कार जीतने वाली लेखिका थीं। इस दौरान दक्षिण एशिया से कोई लेखक पुरस्कार नहीं जीत सका।

कार्सन की लेखन शैली की विशेषता-

कार्सन की वर्ष 1986 में प्रकाशित दीर्घ निबंधात्मक कृति 'इरोस द बिटरस्वीट' उनके आगे के साहित्यिक लेखन की आधारशिला मानी जाती है। इसमें उन्होंने प्रेम के देवता इरोस को कविता का मूल तत्व और उसकी प्रेरक शक्ति बताते हुए प्रेम में निहित सुख और पीड़ा के द्वंद्व का विश्लेषण किया है। सैफो की एक अभिव्यक्ति से प्रेरित यह कृति प्रेम करने वाले और प्रेम पाने वाले के बीच की दूरी को प्रेम की शक्ति का प्रमुख स्रोत मानती है। कार्सन की लेखन शैली की विशेषता विभिन्न आवाजों, दृष्टिकोणों और साहित्यिक परंपराओं को एक साथ प्रस्तुत करना है। वह इसे ऐसी दृष्टि के रूप में देखती हैं, जिसमें दो अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों को एक साथ संतुलित रखा जा सके। उनकी कृति इकोनॉमी ऑफ द अनलॉस्ट (1999) में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी कवि सिमोनाइड्स ऑफ कीओस की तुलना पॉल सेलान से की गई है। वहीं, मेन इन द ऑफ आवर्स (2000) में इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स और लेखिका वर्जीनिया वूल्फ के विचारों को एक साथ रखा गया है। इस तरह के अप्रत्याशित साहित्यिक संयोजनों के माध्यम से कार्सन ने आत्मकेंद्रित कथात्मक कविता की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा और समकालीन साहित्य में नए प्रयोगों को प्रेरित किया। उनका लेखन प्राचीन और आधुनिक कविता के साथ-साथ विभिन्न साहित्यिक विधाओं तथा कला रूपों के बीच सहज आवाजाही करता है। वर्ष 1990 के दशक में कार्सन ने कई उल्लेखनीय कृतियां प्रकाशित कीं। इनमें ग्लास, आयरनी एंड गॉड (1995) संग्रह में शामिल दीर्घ कविता द ग्लास एसे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह रचना कविता, कथा और निबंध के बीच की सीमाओं को धुंधला करती है।

कविता के रूप में लिखी गई यह कृति दुख, विरह और एकतरफा प्रेम की कहानी भी है। इसमें एक महिला, जिसे उसका पति छोड़ चुका है, अपनी अकेली मां से मिलने के लिए निर्जन दलदली क्षेत्र की यात्रा करती है। इस यात्रा में वह अपनी प्रिय लेखिका एमिली ब्रॉन्टे की रचनाएं साथ ले जाती है। ब्रॉन्टे की रचनाओं में वर्णित प्राकृतिक परिवेश और उनकी आंतरिक दुनिया कविता में इस तरह समाहित होते हैं कि तीन अकेली महिलाओं के जीवन और अनुभवों के माध्यम से परित्याग तथा अकेलेपन की पड़ताल की जाती है। कार्सन की विशिष्ट शैली में कविता और कहानी एक-दूसरे को अर्थ प्रदान करते हैं। कार्सन ने एक बार ऊब को अपना सबसे बड़ा शत्रु बताया था। अपने लेखन में वह हास्य, तीखे व्यंग्य और बुद्धिमत्तापूर्ण विडंबना के माध्यम से इसका मुकाबला करती हैं। कार्सन की वर्ष 2010 में प्रकाशित कृति नॉक्स उनके सबसे मार्मिक कार्यों में से एक है। यह उन्होंने अपने भाई माइकल की स्मृति में लिखी थी, जिनकी वर्ष 2000 में डेनमार्क में मृत्यु हो गई थी। उनकी अनुपस्थिति और मृत्यु से जुड़ा रहस्य इस रचना की भावनात्मक पृष्ठभूमि बनता है। नॉक्स साहित्यिक रचना होने के साथ-साथ एक कलात्मक संरचना भी है। यह एक डिब्बे के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें अकॉर्डियन की तरह खुलने वाली पट्टी पर तस्वीरें, पत्र और अन्य लिखित सामग्री शामिल हैं। ये सभी सामग्री दिवंगत भाई की स्मृतियों को सहेजती हैं।

एक नजर

रामविलास पासवान की छठी पुण्यतिथि पर लोजपा (रामविलास) ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम

किशनगंज। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान की छठी पुण्यतिथि पर गुरुवार को लोजपा (रामविलास) के जिला कार्यालय हलीम चौक, दर्जी बस्ती में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हबीबुर रहमान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचार और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। वहीं युवा जिलाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान देश के दलित, वंचित और असहाय लोगों की मजबूत आवाज थे। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हुए आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी और कई महत्वपूर्ण बदलावों में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि संचार क्षेत्र में आम लोगों तक मोबाइल सेवा की पहुंच बढ़ाने तथा रेलवे में गरीबों और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में पासवान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उनका 12 जनपथ स्थित आवास हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहता था। जनता की समस्याएं सुनना और जरूरतमंदों की सहायता करना उनकी राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा था। कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने और 'एक देश, एक राशन कार्ड' जैसी पहल को आगे बढ़ाने में भी रामविलास पासवान के योगदान को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि पासवान ने छह प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और करोड़ों युवाओं तथा आम लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि यह उनके प्रति सम्मान का महत्वपूर्ण प्रतीक होगा।

शालिमार वर्क्स को नहीं मिल रहा जहाज निर्माण का काम, मंत्री ने लिया जायजा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन शालिमार वर्क्स लिमिटेड को पहले की तरह जहाज निर्माण के काम के ठेके नहीं मिल रहे हैं। एक के बाद एक काम के ठेके रद्द होने और कर्मचारियों के वेतन बकाया रहने से कारखाने की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कर्मचारियों की ओर से परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष समस्या के समाधान और कारखाने के बुनियादी ढांचे के विकास की मांग रखी गई थी। इसके बाद गुरुवार को मंत्री ने कारखाने का दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। गंगा नदी के किनारे फोरशोर रोड पर स्थित शालिमार वर्क्स लिमिटेड पिछले कुछ वर्षों से पहले की तरह जहाज निर्माण के ठेके नहीं पा रहा है। इसके कारण कारखाना धीरे-धीरे बदहाल स्थिति में पहुंच रहा है। कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री से कारखाने के बुनियादी ढांचे के विकास की मांग की है।

कारखाने के कर्मचारी रवि बर्धन ने आरोप लगाया कि कारखाने पर प्रबंधन की ओर से अब पहले की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाज निर्माण के कई ठेके रद्द हो रहे हैं और कर्मचारियों के लाखों रुपये वेतन के रूप में बकाया हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने मंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं और मंत्री ने पूरी स्थिति सुनने के बाद सुधार का आश्वासन दिया है। गुरुवार को परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने पहले कारखाने का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि यह कारखाना परिवहन विभाग के अधीन है और वर्तमान में यहां कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने पूरी व्यवस्था को खराब कर दिया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि कुछ कर्मचारी बुधवार को उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आए थे। इसलिए उन्होंने पहले स्वयं कारखाने की स्थिति देखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब कारखाने की स्थिति देखने के बाद आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि यह कारखाना पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय लोगों के लिए एक संपत्ति है। इतनी बड़ी संपत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस कारखाने का उचित उपयोग किया जाएगा। हालांकि, कारखाना प्रबंधन ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

सत्ता में 2047 तक आने वाले नहीं राहुल और उनके दोस्त अखिलेश यादव : केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज। राहुल गांधी और उनके दोस्त अखिलेश यादव वर्ष 2047 तक सत्ता में आने वाले नहीं हैं। प्रदेश में विकास की नई धारा बह रही है और सुशासन की नींव मजबूत हुई है। स्नातक एमएलसी चुनाव में पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता जुटे और भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने के कड़ी मेहनत करें। यह बातें गुरुवार को केपी कम्यूनिटी सेंटर में आयोजित प्रयागराज में स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर आयोजित जिला समन्वयक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं। उन्होंने इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव राज्यसभा में तीसरा प्रत्याशी उतारने की बात करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके विधायकों में भगदड़ मच गई है तो उन्होंने तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारा। उन्होंने दावा किया कि स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। ईवीएम और निर्वाचन आयोग को लेकर विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि जब विपक्ष चुनाव हारता है तो उसका दोष ईवीएम पर डाल देता है, जबकि चुनाव जीतने पर वही प्रक्रिया सही लगती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्नातक एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, प्रदेश की जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पार्टी को और मजबूत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने और संगठन की तैयारियों को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनिल भदौरिया, कुश श्रीवास्तव, विजय द्विवेदी और अशोक पटेल ने मंच से भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह राठौर के समर्थन की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, एमएलसी चुनाव सह संयोजक मानवेंद्र सिंह, सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. बीके सिंह, महापौर गणेश केसरवानी, जिलाध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, यमुनापार जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, गुरु प्रसाद मौर्य, पीयूष रंजन निषाद, राजमणि कोल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, नीरज त्रिपाठी, अमरनाथ यादव, कन्हैया लाल पांडेय, शिवदत्त पटेल, शिखा रस्तोगी, रूपम त्रिपाठी, ज्योति केसरवानी, मनोज निषाद, अनिरुद्ध सिंह पटेल, विनोद तिवारी, शैलेंद्र पांडेय, बृजेश त्रिपाठी, आशीष केसरवानी, अरुण मिश्रा, तुलसी राम सरोज, राजू पाल, आशीष प्रजापति, उमेश तिवारी, विवेक मिश्रा, आत्मधर दुबे, दीपक परासर, विश्व गौरव सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन अवधेश चंद्र गुप्ता ने किया।

बंगाल सरकार ने वापस लिया फैसला, डीएमएस और डीएचएमएस डॉक्टरों को फिर मिला जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी (डीएमएस) और डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (डीएचएमएस) के चिकित्सकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार पुन: बहाल कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

यह फैसला बुधवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय 'स्वास्थ्य भवन' के सामने हुए बड़े प्रदर्शन के बाद लिया गया है। गुरुवार को विभाग की और से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। विभिन्न संघों के बैनर तले सैकड़ों डीएमएस और डीएचएमएस डॉक्टरों ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा था। सूत्रों के अनुसार, डीएमएस डॉक्टरों को पहली बार 1964 में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि, बाद में डीएचएमएस पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद यह अधिकार वापस ले लिया गया था, लेकिन चिकित्सकों के लंबे आंदोलन के बाद वर्ष 1999 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। विवाद तब फिर से गरमा गया जब इसी साल नौ जुलाई को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर इन शक्तियों को एक बार फिर रद्द कर दिया। इस फैसले से पूरे राज्य में तीखी प्रतिक्रिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का तर्क था कि डीएमएस और डीएचएमएस योग्यता वाले चिकित्सकों को वर्षों के आंदोलन के बाद 'द्वितीय अनुसूची' (सेकंड शेड्यूल) में शामिल किया गया था और वे कानूनी रूप से ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार हैं। उन्होंने जुलाई की अधिसूचना को अनुचित, तर्कहीन और अलोकतांत्रिक करार दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 'मेडिकल सर्विस सेंटर' के एक पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 34 हजार डीएमएस और डीएचएमएस डॉक्टर कार्यरत हैं। जुलाई में स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना ने उनके भविष्य को गहरी अनिश्चितता में धकेल दिया था और लोग हमारी पेशेवर विश्वसनीयता पर संदेह करने लगे थे। दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में डीएमएस और डीएचएमएस चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं।

फ्लिपकार्ट ने की 'द बिग बिलियन डेज 2026' की धमाकेदार शुरुआत

नई दिल्ली। बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट हेडक्वार्टर में फ्लिपकार्ट के 'द बिग बिलियन डेज़ 2026' की शुरुआत हुई। भारत के स्वदेशी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने अपने बेंगलुरु कैंपस में 'द बिग बिलियन डेज (टीबीबीडी)' के 13वें संस्करण की शुरुआत की। इसके साथ ही देश के सबसे बहुप्रतीक्षित फेस्टिव शॉपिंग आयोजनों में से एक के लिए मंच तैयार हो गया है। फेस्टिव सीजन की प्रतीकात्मक शुरुआत करते हुए हेमंत बद्री, एसवीपी एवं हेड ऑफ सप्लाई चेन, ने फ्लिपकार्ट विशमास्टर्स के काफिले को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही देशभर में ग्राहकों तक लाखों फेस्टिव डिलीवरी पहुंचाने की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। इस आयोजन में भारतीय अभिनेत्री अनीत पड्डा भी शामिल हुईं और फ्लिपकार्ट की टीम के साथ टीबीबीडी 2026 की शुरुआत का जश्न मनाया।

कंपनी ने जारी बयान में बताया कि फ्लिपकार्ट के लीडर्स और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। कंपनी की टीमें फेस्टिव सीजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटी हैं। कार्यक्रम में कल्याण कृष्णमूर्ति, सीईओ, फ्लिपकार्ट ग्रुप; रवि अय्यर, एसवीपी एवं सीएफओ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स; सीमा नायर, सीएचआरओ; साकेत चौधरी, एसवीपी एवं हेड ऑफ मार्केटप्लेस; बालाजी त्यागराजन, सीपीटीओ; हेमंत बद्री, एसवीपी एवं हेड ऑफ सप्लाई चेन; और रजनीश कुमार, चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर समेत फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा, 'द बिग बिलियन डेज़ भारत की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन चुका है। यह ग्राहकों और सेलर्स को ऐसे बड़े पैमाने पर एक साथ लाता है, जो हमारे बाजार की खासियत भी है। देशभर के 14 लाख से अधिक सेलर्स हमारी सप्लाई चेन की व्यापक पहुंच और क्षमता के माध्यम से अपने उत्पादों को लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हर संस्करण के साथ यह अवसर और व्यापक हुआ है। इससे अधिक छोटे कारोबार डिजिटल कॉमर्स से जुड़े हैं और छोटे शहरों के ग्राहकों को भी ज्यादा विकल्प मिले हैं। जैसे-जैसे भारत की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे द बिग बिलियन डेज़ का दायरा भी बढ़ रहा है और हमें इस सफर का हिस्सा होने पर गर्व है।' द बिग बिलियन डेज (टीबीबीडी)' का विशाल स्तर फ्लिपकार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर्स, सॉर्टेशन फैसिलिटीज और लास्ट-माइल हब्स में दिखाई देता है, जहां हजारों फ्रंटलाइन कर्मचारी अलग-अलग भूमिकाओं में फेस्टिव सीजन के दौरान ऑपरेशंस को सुचारु रूप से चलाने में योगदान देते हैं। इस दौरान विभिन्न लोकेशंस पर डेली हडल्स, माइलस्टोन एक्टिविटीज, स्थानीय स्तर की पहल और कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य टीमों को जोड़ना और बड़े पैमाने पर ग्राहकों तक त्योहारों की खुशियां पहुंचाने में उनके योगदान को सम्मान देना है। फेस्टिव सीजन के दौरान कर्मचारियों की सेहत और उनके लिए जरूरी सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया : डॉ जितेन्द्र सिंह

नमो बुक फेस्ट में विकसित भारत 2027 विषय पर युवाओं और वैज्ञानिकों में संवाद, केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह भी हुए शामिल

वाराणसी, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवैधानिक पदों पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय 'नमो बुक फेस्ट' के अन्तिम दिन गुरूवार को विकसित भारत 2027 विषय पर युवाओं और वैज्ञानिकों के बीच संवाद हुआ। सिगरा स्थित रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जुटे युवाओं ने जमकर सवाल पूछे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह भी शामिल हुए। समापन समारोह में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता टेक्नोलॉजी को दी है। स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया है, जिससे स्पेस इकोनॉमिक्स की पहले से बेहतर तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नागरिक भी रोजगार के लिए विदेशों में अपना परिचय भारतीय के रूप में देता है। एक छात्र द्वारा एआई से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल जरूरी है और एआई को भी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने छात्रों से सरकारी वेबसाइटों के लिए सुझाव भी मांगे।

कार्यक्रम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने गंगा ट्रीटमेंट प्लांट पर चर्चा करते हुए बताया कि नमामि गंगे मिशन के तहत नई टेक्नोलॉजी से गंगा स्वच्छता पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें युवाओं और वैज्ञानिकों की भूमिका अहम है। समापन कार्यक्रम में लेखक अमीश त्रिपाठी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने काशी, गंगा और लेखन पर विशेष चर्चा की। इस दौरान काशी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'काशी बियॉन्ड द घाट' दिखाई गई, जिसमें काशी की संस्कृति और गंगा के महत्व को दर्शाया गया। युवाओं से संवाद के दौरान वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। छात्रों ने एआई से जुड़े सवाल पूछे। अन्य वक्ताओं में आरजे रौनक ने कहा कि जेन-जी कर्म करो, सुजैन ने कहा कि लोकल बनो फिर वोकल बनो, युवराज पोखरना ने बताया कि देश में 300 से 3 लाख स्टार्टअप हो गए हैं, अंशु गुप्ता ने कहा कि भारत नॉन-अलाइन से ऑल-अलाइन बना है। बताते चले इस फेस्ट का आयोजन काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च काशी ने किया। फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई 500 से अधिक पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न लेखकों की रखी गई थी। ये पुस्तकें मोदी सरकार की कार्य पद्धति और नीतियों का ब्लू प्रिंट हैं। आयोजक संस्था के पदाधिकारी व वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम कई विश्व कीर्तिमान हैं। एक अनूठा कीर्तिमान यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी समकालीन वैश्विक नेताओं में ऐसे नेता हैं जिनके व्यक्तित्व, जीवन और नीतियों पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं। फेस्ट के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे और उनके साथ आया प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ।

भारत की औद्योगिक वृद्धि का इंजन बनेगी जेन-जी : डॉ. अभिषेक वर्मा

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में देश की युवा पीढ़ी, विशेषकर जेन-जी, की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। युवाओं को तकनीक के केवल उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, कुशल पेशेवर और रोजगार सृजक के रूप में आगे आना होगा। यह बात शिवसेना-एनडीए गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक और सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉ. अभिषेक वर्मा ने कही।

दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन के सहयोग से सेंटर फॉर नमो स्टडीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में 'टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता से इनोवेशन करने वाले बनने तक: विकसित भारत 2047 के निर्माण में जेन-जी की भूमिका' विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, पेशेवरों, फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। डॉ. अभिषेक वर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और अन्य उभरती तकनीकों के विस्तार के साथ कार्यस्थलों की प्रकृति तेजी से बदल रही है। ऐसे में युवाओं के लिए लगातार सीखते रहना, नई स्किल हासिल करना और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर, एप्लाइड रिसर्च और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के अधिक अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे कक्षा में हासिल ज्ञान को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़ सकें। उनके अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार तलाशने वालों के साथ-साथ रोजगार पैदा करने वालों के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। डॉ. वर्मा ने कहा कि औद्योगीकरण को केवल बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। पारंपरिक उद्योगों, स्थानीय उद्यमों और उभरते व्यवसायों में भी डिजिटल तकनीक और आधुनिक टूल्स के इस्तेमाल से उत्पादकता तथा बाजार तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है। इस क्षेत्र में जेन-जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के ग्रुप कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रेसिडेंट डॉ. विनोद के. वर्मा ने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ संवाद कौशल, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच, टीमवर्क और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता भी आज के कार्यक्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत संबंध विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दयारानी वेलनेस की मेंटर एवं फाउंडर तथा रिलायंस की पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रीति श्रीवास्तव ने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, लगन और समस्या समाधान की क्षमता को युवाओं के लिए आवश्यक बताया। वहीं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फ़िरोज़ बख्त अहमद ने भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और इनोवेशन के महत्व पर विचार रखे। सेंटर फॉर नमो स्टडीज के चेयरमैन प्रो. जसीम मोहम्मद ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश के लिए बड़ी ताकत है, लेकिन यह जनसांख्यिकीय लाभ तभी विकास की मजबूत शक्ति में बदल सकता है, जब युवाओं को उचित कौशल, अवसर और संस्थागत सहयोग मिले। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रो. जसीम मोहम्मद ने एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, इनोवेशन, रोबोटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रमुख क्षेत्र बताया, जिनमें युवा अपनी क्षमता का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रो. दिव्या तंवर ने किया। माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल प्रो. हरप्रीत कौर ने स्वागत भाषण दिया, जबकि सेंटर फॉर नमो स्टडीज की तुषिता भंडारी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए कुशल, अनुशासित, नवाचारी और उद्यमशील सोच वाली युवा पीढ़ी की भी आवश्यकता होगी। जेन-जी की तकनीकी समझ और रचनात्मक क्षमता भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स की शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत, फायदे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली, एजेंसी। प्लास्टिक जॉइनिंग और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रदान करने तथा बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) मॉडल से जुड़ी कंपनी एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट ने मजबूती के साथ एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 67 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 10.75 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 74.20 रुपये के स्तर पर हुई।

मजबूत लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बनने पर ये शेयर कुछ देर के लिए फिसल कर 73 रुपये के स्तर पर आ गया। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे इसकी चाल में तेजी आ गई। खरीदारी के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 77.91 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गया। हालांकि, इस स्तर पर मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण कुछ देर में ही अपर सर्किट ब्रेक हो गया। दिन भर हुई खरीद बिक्री के बाद ये शेयर 73 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इस तरह पहले दिन के कारोबार कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 6 रुपये यानी 8.96 प्रतिशत का मुनाफा हो गया था। कंपनी का 23.45 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.82 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 2.63 गुना सब्सक्रिप्शन आया था।

रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.01 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 35,00,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनरी की खरीदारी करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, पुराने कर्ज के बोझ को हल्का करने, आईपीओ से जुड़े खर्चों की भरपाई करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में लगातार मजबूती आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 3.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 4.17 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 5.24 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 15.22 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़त के साथ 21.15 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 26.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)